Discover your divinity with us
A/C Showroom
ज्ञान गंगा ॐ मूर्ति माला केन्द्र
उजाला भवन स्टेशन रोड, दुर्ग
0788-4030383, 3293199

भगवान के वस्त्र, श्रृंगार मूर्तियां एवं समस्त पूजन सामग्री संगमरमर व पीतल की मूर्तियां राशि रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध

राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...
रायपुर एवं दुर्ग से प्रकाशित

समय दर्शन

ESTD : Since 2011

संस्थापक : स्व. श्रीमती निलिमा खड़तकर
निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ

दुर्ग शहर में सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य
पं. एम.पी. शर्मा/
मो. 8109922001
फीस 251/- मात्र
पताः- श्री दुर्गा ज्योतिष कार्यालय सिकोला भाठा, सब्जी मार्केट के सामने, धमधा नाका, दुर्ग

वर्ष 15, अंक 100 | पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रूपये | दुर्ग, शनिवार 21 फरवरी 2026 | www.samaydarshan.in

जल संरक्षण को दिनचर्या का हिस्सा बनाने, जल संरचनाओं की रक्षा और जल के प्रति जिम्मेदार सोच अपनाने का मुख्यमंत्री ने किया आह्वान

राज्य सरकार जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध - मुख्यमंत्री साय

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों और नवाचारों की सराहना की

31 मई तक 10 लाख जल संरचनाओं का लक्ष्य, जल सुरक्षा को मिलेगा नया आधार

रायपुर (समय दर्शन)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की संयुक्त अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश में जल संचय-जन भागीदारी 2.0 अभियान के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए और बैठक को संबोधित किया। इस दौरान बिलासपुर, दुर्ग और सूरजपुर जिले के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यों और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जल संकट 21वीं सदी की केवल गंभीर पर्यावरणीय ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक चुनौती भी बन चुका है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए जनभागीदारी अनिवार्य है।उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश का उल्लेख किया, जिसमें पानी के उपयोग को प्रसाद के समान मानते हुए जल के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर राज्य सरकार जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अभियान के दूसरे चरण जल संचय-जन भागीदारी 2.0 के अंतर्गत तकनीक आधारित और अधिक परिणाममूलक रणनीति अपनाई जा रही है। राज्य सरकार ने 31 मई 2026 तक 10 लाख जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने इसे जल सुरक्षा की दिशा में प्रदेश का ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक विशेष पहल के तहत 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले चार लाख से अधिक किसानों को अपने खेतों में डबरी निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कार्य में जिला प्रशासन के साथ-साथ औद्योगिक समूहों का सहयोग भी लिया जा रहा है। इन डबरियों से भू-जल स्तर में वृद्धि के साथ किसानों को सिंचाई एवं मछली पालन जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में सभी जल संरचनाओं की जियोटैगिंग, ग्राम पंचायतों के वॉटर बजट तथा जल सुरक्षा योजनाओं के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही गांवों के युवाओं को जल मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि अभियान को गति मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि क्रिटिकल और सेमी-क्रिटिकल ब्लॉकों पर विशेष फोकस रखते हुए सेमी-क्रिटिकल ब्लॉकों में 40 प्रतिशत तथा क्रिटिकल ब्लॉकों में 65 प्रतिशत जल संरक्षण कार्यों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

5 क्रिटिकल और 21 सेमी-क्रिटिकल भू-जल ब्लॉक चिन्हित

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अभियान के पहले चरण में छत्तीसगढ़ ने देशभर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा विभिन्न जिलों को भी अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार मिले। पहले चरण में सामुदायिक भागीदारी के मॉडल पर कार्य करते हुए बड़े पैमाने पर बोरवेल रिचार्ज, रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज शाफ्ट, सोक पिट और ओपनवेल रिचार्ज जैसी संरचनाओं का निर्माण किया गया। श्री साय ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 5 क्रिटिकल और 21 सेमी-क्रिटिकल भू-जल ब्लॉक चिन्हित हैं। वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में इनमें से 5 ब्लॉकों में भू-जल निकासी में कमी और भू-जल स्तर में सुधार दर्ज किया गया है, जो जल संरक्षण प्रयासों के सकारात्मक परिणामों का संकेत है।

केंद्र की सौगात : चंडीगढ़-मोहाली-पंचकूला के लिए 6-लेन स्पर प्रोजेक्ट मंजूर, रवनीत सिंह बिट्टू ने जताया आभार

चंडीगढ़ (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए एक बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एनएच-205ए के अंबाला-चंडीगढ़ सेक्शन को जीरकपुर बाईपास से जोड़ने वाले 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड स्पर के निर्माण के लिए 1,463.95 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस योजना पर खुशी जाहिर की और केंद्र सरकार का आभार जताया। यह प्रोजेक्ट ट्राइसिटी रिंग रोड (चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला) का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो क्षेत्र की यातायात समस्याओं को काफी हद तक हल करने वाला साबित होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस प्रोजेक्ट की जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि यह कॉरिडोर मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकूला के मुख्य शहरी चौराहों पर ट्रैफिक को डायवर्ट करके भीड़ कम करेगा।

उन्होंने बताया कि इससे एनएच-44, एनएच-205ए और एनएच-152 पर भारी वाहनों का दबाव घटेगा। खास तौर पर हिमाचल प्रदेश, विशेषकर शिमला क्षेत्र की ओर जाने वाले यात्रियों को तेज और आसान कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा और क्षेत्रीय आर्थिक जुड़ाव मजबूत होगा। यह प्रोजेक्ट सड़क सुरक्षा बढ़ाने, प्रदूषण कम करने और आर्थिक विकास को गति देने में मददगार साबित होगा।

पंजाब से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, पंजाब की तरक्की को प्राथमिकता देने के लिए गडकरी जी का शुक्रिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, एएसआई को दाखिल करना होगा जवाब

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस

प्रयागराज (एजेंसी)। श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मामले में शुक्रवार दोपहर 2 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) शुक्रवार को अपना जवाब दाखिल करेगी। इसके बाद रिपोर्ट पर दोनों पक्ष बहस में शामिल हो सकते हैं। हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर वर्तमान में सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और भूमि पर कब्जे की मांग की गई है। मस्जिद पक्ष ने 22 अगस्त को सीपीसी की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें समेकित मुकदमों की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। बता दें कि इससे पहले 30 जनवरी को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मस्जिद प्रकरण में तीन घंटे तक सुनवाई चली थी, जिसमें जस्टिस अविनाश सक्सेना की अदालत में सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को दी थी।

सुनवाई के दौरान श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस के हिंदू पक्षकार एवं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत को बताया था कि मुकदमा संख्या तीन में अब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल नहीं की गई है। इस पर एएसआई ने जवाब दिया था कि रिपोर्ट और जवाब देने के लिए उन्हें दो सप्ताह का समय जरूरी है, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 फरवरी को तय कर दी थी।

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में औरंगजेब के शासनकाल में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बने प्राचीन केशवदेव मंदिर को तोड़कर किया गया था। उनका कहना है कि यह स्थल भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 20 लाख की फिरौती मांगने वाले गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई के विलेपार्ले इलाके में एक ज्वेलरी कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकाकर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। लेकिन, पुलिस की सतर्कता और चालाकी से यह साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चार युवकों को 5 लाख रुपए नकद के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फरियादी विलेपार्ले पूर्व में मंगल रॉयल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से ज्वेलरी का कारोबार करते हैं। 12 फरवरी की रात उन्हें एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप संदेश मिला, जिसमें लिखा था कि 20 लाख रुपए नकद चाहिए, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। संदेश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग, कनाडा का नाम लिया गया था। इसके बाद लगातार धमकी भरे संदेश और कॉल आने शुरू हो गए। 14 फरवरी को व्हाट्सएप कॉल पर खुद को गैंग का सदस्य बताने वाले व्यक्ति ने फिर 20 लाख की मांग दोहराई।

कारोबारी ने पैसे न होने की बात कही तो सौदेबाजी शुरू हुई और रकम 5 लाख पर तय हो गई। 15 फरवरी को फिर कॉल आया कि पैसा तैयार रखें। रात में कारोबारी ने संदेश भेजा कि उनके पास सिर्फ 3 लाख हैं।

बंगाल एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा- सीजेएम हटाकर पुराने जजों को खोजें

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में निर्वाचन आयोग की तरफसे कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उपजे विवाद के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफजस्टिस को कई अहम निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि एसआईआर के काम में लगाए गए सीजेएम को हटाकर पुराने जजों को तलाशें।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि न्यायिक अधिकारियों को राहत दें और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के काम में सहायता के लिए पूर्व न्यायाधीशों को नियुक्त करने की दिशा में काम करें। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के लिए पर्याप्त 'ए' श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति न करने का भी संज्ञान लिया।

मामले में कोर्ट ने क्या-क्या निर्देश दिए, समझिए

जिन लोगों के नाम तार्किक विसंगति सूचीमें डाले गए हैं, उनके दावे और आपत्तियों का फैसला अब सेवारत और पूर्व न्यायिक अधिकारी करेंगे। कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा है कि वे इस काम के लिए न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध कराएं और जरूरत पड़े तो पूर्व जजों को भी नियुक्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस काम में लगे सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) को हटाकर अन्य उपयुक्त न्यायिक अधिकारियों/पूर्व जजों को लगाया जाए। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पर्याप्त 'ए' श्रेणी के अधिकारियों को तैनात न करने पर गंभीर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 28 फरवरी को बंगाल की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी है।

साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर बाद में पूरक (सप्लीमेंट्री) सूची भी जारी की जा सकती है।

अदालत ने पश्चिम बंगाल के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को निर्देश दिया है कि वे एसआईआर प्रक्रिया में लगे न्यायिक अधिकारियों को लॉजिस्टिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। एसआईआर प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों की मदद के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर और राज्य सरकार के अधिकारी भी तैनात रहेंगे।

पाकिस्तान ने अपने ही जवानों को दिया धोखा

बलूचिस्तान में बंधक सैनिकों को पहचानने से किया इनकार, खतरे में जान

इस्लामाबाद(एजेंसी)। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने जवानों को धोखा दिया है। पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर मुसीबत में फंसे अपने जवानों के अस्तित्व को ही नकार दिया। दरअसल 14 फरवरी को बलूच लिबरेशन आर्मी ने तस्वीरें और वीडियो जारी करके दावा किया कि उसने पाकिस्तान सेना के सात जवानों को पकड़ लिया है। संगठन ने साफ कहा कि उनके साथियों को छोड़ो, वरना 21 फरवरी के बाद इन सैनिकों को मार दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान को सीधा सीधा अल्टीमेटम।

पाकिस्तान कर रहा ये दावा

ये वीडियो सामने आते ही पाकिस्तान सेना की दसवीं कोर और इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव हो गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वीडियो फर्जी है, डिजिटल छेड़छाड़ की गई है और जो लोग दिख रहे हैं वे पाकिस्तानी सैनिक नहीं हैं। देखते ही देखते ऑनलाइन नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू हो गई और इसे 'इन्फॉर्मेशन वॉर' बताया गया।

इस बीच पाकिस्तान के एक रोते सिपाही का वीडियो सामने आया जो आर्मी से जुड़े अपने दस्तावेज दिखा रहा है। उच्च पदस्थ रक्षा सूत्रों ने बताया कि मामला तब और गंभीर हो गया जब एक नया वीडियो सामने आया। उसमें सातों लोग साथ बैठे दिखे और अपने-अपने आर्मी सर्विस कार्ड कैमरे पर दिखाए। मोहम्मद शाहराम नामक एक सिपाही तो साफतौर पर भावुक नजर आया। उसने अपना सैन्य पहचान पत्र और नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का राष्ट्रीय पहचान पत्र दिखाते हुए पूछा, अगर ये असली नहीं हैं तो इन्हें जारी किसने किया?

उन्होंने बताया कि वह अपने घर के सबसे बड़े बेटे हैं। उनके पिता दिव्यांग हैं और परिवार पूरी तरह उन पर निर्भर है. उनका दर्द साफदिख रहा था। उन्होंने पाकिस्तानी सेना से सीधा सवाल किया, अगर हम सेना से नहीं हैं, तो भर्ती किसने की?

बलूच लिबरेशन आर्मी ने जारी किए तस्वीरें और वीडियो जारी

15 फरवरी को बलूच लिबरेशन आर्मी ने तस्वीरें और वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने पाकिस्तान सेना के सात जवानों को हिरासत में लिया है। वीडियो सामने आते ही पाकिस्तान सेना का आधिकारिक नैरेटिव यह था कि वीडियो में दिख रहे लोग पाकिस्तानी सैनिक नहीं हैं और फुटेज डिजिटल रूप से छेड़छाड़ कर तैयार किया गया है। यहां बलूच लिबरेशन आर्मी के दावों को मनगढ़ंत प्रचार बताया गया।

इस बीच बलूच लिबरेशन आर्मी ने दो अन्य व्यक्तियों के वीडियो भी साझा किए। इनकी पहचान दीदार उल्लाह और उस्मान के रूप में कराई गई। दोनों ने खुद को पाकिस्तान सेना का सेवारत जवान बताया और अपने दस्तावेज दिखाए। इस सब के बीच 21 फरवरी की समय-सीमा करीब आती जा रही है। संगठन ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि यदि इस्लामाबाद बातचीत शुरू नहीं करता है और इन सैनिकों को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करता है, तो परिणाम गंभीर होंगे।

रक्षा सूत्रों का कहना है कि इस बीच पाकिस्तान की ओर से स्पष्ट और औपचारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे अटकलों और चर्चाओं को और बल मिला है।

ब्रिटेन ने अमेरिका को एयरबेस देने से किया इनकार

फैसले से डोनाल्ड ट्रम्प नाराज

लंदन(एजेंसी)। ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपने एयरबेस देने से मना कर दिया है। अमेरिका इन सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन ने इनकार कर दिया।

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन के इस फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नाराज हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के उस समझौते से समर्थन वापस ले लिया है, जिसमें चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस को सौंपने की बात थी।

रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वह डिएगो गार्सिया और ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस का इस्तेमाल करना चाहता है। डिएगो गार्सिया, चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। 1970 के दशक से यह ब्रिटेन और अमेरिका का साझा सैन्य अड्डा रहा है।

दरअसल पुराने समझौतों के मुताबिक, ब्रिटेन के किसी भी सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल तभी हो सकता है, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसकी मंजूरी दें। अंतरराष्ट्रीय कानून भी कहता है कि अगर कोई देश जानता है कि सैन्य कार्रवाई गलत है और फिर भी मदद करता है, तो उसे भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

ट्रम्प बोले- चागोस आइलैंड्स छोड़ना बहुत बड़ी गलती

ट्रम्प ने चागोस आइलैंड्स को लेकर ब्रिटेन की आलोचना की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर गुरुवार को लिखा कि 100 साल की लीज किसी देश के मामले में ठीक फैसला नहीं है। डिएगो गार्सिया जैसा ठिकाना छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। ट्रम्प ने कहा कि अगर ईरान, अमेरिका के साथ समझौता नहीं करता, तो अमेरिका को हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया और फेयरफोर्ड के एयरफील्ड का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसे में इन ठिकानों का कंट्रोल बेहद जरूरी है।

संक्षिप्त समाचार

हरियाणा का बजट 2 मार्च को होगा पेश, कई योजनाओं का विस्तार कर सकती है भाजपा सरकार

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। यह 18 मार्च तक चलेगा। सत्र के पहले दिन शुक्रवार को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। वहीं, विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। हरियाणा सरकार के अनुसार, सदन की कार्यवाही में पहले दिन शोक प्रस्ताव के जरिए दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। बजट सत्र की कार्यवाही में 21 और 22 फरवरी को अवकाश रहेगा। इसके बाद 23 फरवरी को सदन 2 बजे शुरू होगा और 24 से 27 फरवरी तक सत्र की बैठकें सुबह 11 बजे शुरू होंगी। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे, जबकि 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही कई दिन चर्चा के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, जबकि 17 मार्च को बजट एस्टीमेट पर वोटिंग होगी। वहीं, बजट सत्र से पहले गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के साथ सभी विधायकों ने हिस्सा लिया था। बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। प्रदेश में ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग करेगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जो 2024-25 से वर्ष से 13.7त्न अधिक था। इस बार बजट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई नई योजनाओं की भी घोषणा करने के साथ पुरानी योजनाओं का विस्तार कर सकते हैं। सरकार लाडो लक्ष्मी योजना की पारिवारिक आय की सीमा भी बढ़ा सकती है।

ईडी की बड़ी कार्रवाई, विंजो और उसकी सहयोगी कंपनी की 590 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने **ऑनलाइन** गेमिंग कंपनी विंजो प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की करीब 590 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के तहत नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। ईडी के बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने कंपनी के बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड बॉन्ड जैसी वित्तीय संपत्तियों को जब्त किया है। जांच में पाया गया कि ये संपत्तियां विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के नियमों के खिलाफ रखी गई थीं। जांच में सामने आया कि विंजो ऑनलाइन रियल मनी गेम्स और जुआ से जुड़े 100 से अधिक गेम संचालित कर रही थी। कंपनी का दावा है कि उसके करीब 25 करोड़ यूजर्स हैं। कंपनी ने विदेश में अपनी सहयोगी कंपनियों, जैसे विंजो यूएस आईएनसी (अमेरिका) और विंजो एसजी पीटीई लिमिटेड (सिंगापुर), में करीब 492 करोड़ रुपए (लगभग 54 मिलियन डॉलर) का निवेश किया था। ईडी की जांच में कई गंभीर तथ्य सामने आए। विदेश में बनाई गई कंपनियों के पास वहां कोई कर्मचारी या वास्तविक ऑफिस नहीं था। इन कंपनियों का पूरा संचालन भारत से ही किया जा रहा था। विदेश में जमा पैसा जुआ और रियल मनी गेम्स जैसी प्रतिबंधित गतिविधियों से कमाया गया था। कंपनी ने विदेशी निवेश के नाम पर पैसा विदेश में रखा, जो नियमों का उल्लंघन है। जांच में सामने आया है कि इन सभी कंपनियों का संचालन भारत से हो रहा था। जांच में पाया गया कि विदेश की कंपनियों के बैंक खाते, अकाउंटिंग और रोजमर्रा के फैसले भारत से ही लिए जा रहे थे। सिंगापुर की कंपनी भारत की कंपनी से गेम का लाइसेंस शुल्क ले रही थी। ईडी के अनुसार, विदेशी सहयोगी कंपनियां ऐसे गेम चला रही थीं जो भारतीय कानून के तहत प्रतिबंधित हैं।

तीसरे फेज में देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगी एसआईआर

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के सचिव पवन दीवान ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लेटर लिखकर एसआईआर से जुड़ी तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने लेटर में बताया कि तीसरे फेज में दिल्ली, कर्नाटक सहित शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। लेटर में आगे कहा गया है कि चुनाव आयोग ने पिछले साल 24 जून को आदेश दिया था कि पूरे देश में एसआईआर किया जाएगा। बता दें चुनाव आयोग ने पहले फेज में बिहार में एसआईआर करवाया था। दूसरे फेज के तहत, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर 2025 से एसआईआर जारी है।

खबर-खास

सारंगढ़ में अवैध रेत उत्खनन का आरोप, कार्रवाई नहीं हुई तो धरना देने की चेतावनी - कांग्रेस

सारंगढ़ (समय दर्शन)। क्षेत्र के रेत घाटों में अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर कांग्रेस परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (स्ड्डरू) को ज्ञापन सौपा है और कहा गया है कि सारंगढ़ अंतर्गत विभिन्न रेत खदानों में लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है तथा लापरवाहीपूर्वक डंपरों के माध्यम से रेत का परिवहन हो रहा है। आगे कहा कि कई वाहनों में नंबर प्लेट तक नहीं है, जिससे नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। साथ ही रेत घाटों पर अवैध वसूली किए जाने का भी आरोप लगाया गया है, जिससे शासन को आर्थिक क्षति पहुंच रही है। कांग्रेस परिवार ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर तत्काल उचित कार्रवाई करने की मांग की है। चेतावनी देते हुए कहा गया है कि यदि शीघ्र प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो कांग्रेस परिवार कार्यालय के समक्ष धरना देने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। ज्ञापन देने पहुंचे जिला कांग्रेस अध्यक्ष ताराचंद देवांगन, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि सुरज तिवारी, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सतीश श्रीवास, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रामनाथ सिदार, जिला पंचायत सदस्य बिनोद भारद्वाज,मण्डल अध्यक्ष राजू यादव, मण्डल अध्यक्ष अश्वनी चंद्रा उपस्थित रहे।

तीन करोड़ से अधिक बकाया भुगतान को लेकर किसानों का उग्र प्रदर्शन,ट्रैक्टर रैली के दौरान आधे घंटे चक्काजाम

महासमुन्द (समय दर्शन)। महासमुंद जिले में किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। करोड़ों रुपये के बकाया भुगतान को लेकर सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर रायपुर कूच करने का प्रयास किया। रैली को बेलसोण्डा के पास रोके जाने के बाद किसान राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर ही धरने पर बैठ गए और करीब आधे घंटे तक चक्काजाम किया। कृषि विभाग और पुलिस अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में बात नहीं बनी। बाद में कृषि विभाग केअधिकारियों द्वारा शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिए जाने पर किसानों ने चक्काजाम समाप्त किया। किसानों का आरोप है कि रबी सीजन 2024-25 में तेलंगाना की कावेरी बीज कंपनी ने उनकी जमीन लीज पर लेकर बीज उत्पादन कराया, मजदूरों से काम कराया और मशीनरी का उपयोग किया, लेकिन अब तक न तो मेहनताना दिया गया और न ही लीज की राशि का भुगतान किया गया।

किसानों के अनुसार 133 किसानों का कुल बकाया ?3,23,26,388 है। जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक 2 प्रतिशत मासिक ब्याज जोड़ने पर यह राशि बढ़कर ?3,74,98,610 हो चुकी है। किसानों की मांग है कि कंपनी प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और जल्द से जल्द पूरा भुगतान कराया जाए। वहीं कृषि विभाग के उप संचालक का कहना है कि जांच में मामला सही पाया गया है और शीघ्र भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

बड़े बकायादारों पर निगम का कड़ा शिकंजा: टेक्स नहीं तो होगी कुर्की की कार्रवाई

दुर्ग (समय दर्शन)। नगर पालिक निगम दुर्ग के आयुक्त सुमित अग्रवाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राजस्व वसूली को लेकर उन्होंने राजस्व अधिकारी आर.के.बोरकर,सहायक राजस्व अधिकारी थानसिंग यादव एवं राजस्व अमले की टीम को कड़े निर्देश जारी किए हैं। स्पष्ट कहा गया है कि बड़े बकायादारों द्वारा टैक्स जमा नहीं करने की स्थिति में सीधे कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त के निर्देश पर राजस्व विभाग ने लंबे समय से बकाया टैक्स नहीं चुकाने वाले बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर ली है। इन बकायादारों से लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक की राशि निगम को प्राप्त करनी है। सहायक राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी विशेष रूप से इन प्रकरणों में लगाई गई है ताकि शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जा सके। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने स्पष्ट कहा है कि यदि करदाता टैक्स जमा करने में आनाकानी करते हैं तो पहले नोटिस जारी किया जाएगा, तत्पश्चात नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। निगम प्रशासन अब किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई के मूड में नहीं है।नगर निगम को लंबे समय से लंबित राजस्व की आवश्यकता विभिन्न विकास कार्यों के लिए है। ऐसे में बड़े बकायादारों से शीघ्र

ई-ऑफिस क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों-कर्मचारियों का व्यापक प्रशिक्षण, पारदर्शिता और गति लाने पर जोर

बेमेतरा (समय दर्शन)। जिले में ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के उद्देश्य से आज दिशा सभाकक्ष (टीएल मीटिंग हॉल), द्वितीय तल, कलेक्टर कार्यालय बेमेतरा में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शासन की मंशा के अनुरूप शासकीय कार्यप्रणाली को पूर्णत: डिजिटल, पारदर्शी, समयबद्ध एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रशिक्षण मे ई ऑफिस नोडल ऑफिसर श्री प्रकाश कुमार भारद्वाज अपर कलेक्टर, श्री गुड्डू लाल जगत अपर कलेक्टर बेमेतरा, श्रीमती पिंकी मनहर डिप्टी कलेक्टर, श्री रोहित कुमार चंद्रवंशी, डी आई ओ एन आई सी एवं श्री महेंद्र कुमार वर्मा ई जिला प्रबंधक उपस्थित थे। प्रशिक्षण में सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर से आए मास्टर ट्रेनर्स सुश्री मुस्कान जडवानी, प्रोजेक्ट इंजीनियर एवं सुश्री पूजा सेनपाल, प्रोजेक्ट इंजीनियर द्वारा ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस एवं स्पैरो पोर्टल के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने डिजिटल फाइल निर्माण, ई-नोटिंग, ई-डिस्पैच, पत्राचार, दस्तावेज अपलोडिंग, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम तथा ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया का चरणबद्ध प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइव डेमो प्रस्तुत कर प्रतिभागियों को व्यवहारिक जानकारी दी गई, जिससे वे अपने-अपने कार्यालयों में प्रणाली का प्रभावी उपयोग कर सकें।

प्रशिक्षण दो पालियों में आयोजित किया गया। प्रथम पाली में प्रात: 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जिले के सभी कार्यालयों (संयुक्त जिला कार्यालय परिसर एवं जिला पंचायत में स्थित कार्यालयों को छोड़कर) के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संयुक्त जिला कार्यालय परिसर एवं जिला पंचायत में स्थित कार्यालयों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भाग लिया।

मोतीपुर- जामगांव एम चौक पर ब्रेकर नहीं, हादसों का बढ़ा खतरा

पाटन (समय दर्शन)। क्षेत्र के मोतीपुर स्थित झीट जामगांव एम चौक के पास ब्रेकर नहीं होने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर वाहन तेज गति से चलते हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे की आशंका बनी रहती है। अब तक कई वाहन आपस में टकरा चुके हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि झीट की ओर ब्रेकर बने होने से वहां कुछ हद तक राहत है, लेकिन जामगांव एम और मोतीपुर खम्हरिया चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर एक-एक ब्रेकर की सख्त आवश्यकता है। इस संबंध में ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

ग्राम सरपंच मोहन लोधी ने बताया कि चौक से आगे जामगांव एम में शराब दुकान स्थित है, जिसके कारण इस मार्ग पर यातायात का दबाव अधिक रहता है। दोपहिया वाहन चालक भी तेज गति से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते ब्रेकर का निर्माण नहीं कराया गया तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने संबंधित विभाग से शीघ्र आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

निरंतर परिश्रम,अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है - डॉ.सुरेश यादव

ज्ञानोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जांजगीर में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण समारोह

जांजगीर (समय दर्शन)। ज्ञानोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जांजगीर में अत्यंत हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में पुरस्कार वितरण एवं सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ, जिससे विद्यालय परिसर में उत्साह का वातावरण निर्मित हुआ।

समारोह में विद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुरेश यादव सहित गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए। अपने प्रेरणादायी संबोधन में प्राचार्य ने कहा कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है। विद्यार्थियों को जीवन में उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए।

नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के हिंदी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम के अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को शील्ड एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों एवं अभिभावकों ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर हर्ष व्यक्त किया। विद्यालय के उन शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने शैक्षणिक, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में विशेष योगदान दिया। उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर विद्यालय परिवार द्वारा सम्मान व्यक्त किया गया।

विद्यालय में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए। विभिन्न सह-शैक्षणिक एवं रचनात्मक गतिविधियों में सहभागिता करने वाले विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन स्वरूप टिफिन, बॉटल, कंपॉक्स आदि उपयोगी उपहार वितरित किए गए। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि खेलकूद एवं अन्य गतिविधियाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता एवं टीम भावना का विकास करती हैं।

समारोह को और भी आकर्षक बनाने हेतु विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियाँ देकर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। देशभक्ति एवं पारंपरिक गीतों पर आधारित प्रस्तुतियों ने सभी को भावविभोर कर दिया तथा दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ तथा विद्यालय परिवार ने भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायी एवं शिक्षाप्रद कार्यक्रम आयोजित करते रहने का संकल्प लिया।

पेंशनर्स राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए छत्तीसगढ़ से 25 पेंशनर प्रतिनिधि हुए रवाना

22 एवं 23 फरवरी को .कुरुक्षेत्र में होगा राष्ट्रीय अधिवेशन

जांजगीर (समय दर्शन)। अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन (ड्डस्नक्क) का 2 रा राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 22 एवं 23 फरवरी 26 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र मे राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड सुरेश चौधरी के नेतृत्व में सम्पन्न होने जा रहा है । उक्त सम्मेलन मे देश के सभी राज्यों से पेशनर्स प्रतिनिधि भाग लेगें.

छत्तीसगढ़ से एक मात्र संगठन प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन फरीदाबाद ,नई दिल्ली से संबद्ध है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन मे छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रान्ताध्यक्ष आर.के.थवाईत के नेतृत्व मे सर्व श्री आर एस छत्री प्रदेश सलाहकार जांजगीर, अरुण कुमार वर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष रायगढ़ , श्री सुंदर सिंह ठाकुर प्रदेश महामंत्री बिलासपुर, देवेंद्र कुमार पटेल प्रदेश महामंत्री रायगढ, सोहन डहरिया प्रदेश संयोजक अभियंता प्रकोष्ठ जांजगीर, अशोक राठौर प्रदेश सचिव जांजगीर ,डी के शर्मा प्रदेश संगठन सचिव, पी आर कौशिक संभागीय संयोजक बिलासपुर, डी आर श्रीवास संभागीय सचिव बिलासपुर, महेश कुमार साव नगर अध्यक्ष बिलासपुर,आर आर यादव बिलासपुर, पी आर सोनी बिलासपुर, मदन सिंह उपाध्यक्ष रायगढ,टीकाराम पटेल रायगढ़, अनंत सिन्हा प्रदेश उपाध्यक्ष अंबिकापुर राष्ट्रीय अधिवेशन मे भाग लेने आज उसलापुर रेलवे स्टेशन से हमसफर एक्सप्रेस से कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए। प्रान्ताध्यक्ष आर.के.थवाईत द्वारा बताया गया कि आज के इस परिस्थिति मे सेवा निवृत्त पेशनरो के कई ज्वलंत समस्याये जैसे समय पर मंहगाई राहत का लाभ राज्य सरकारो द्वारा नही दिया जाना, कैसलेस चिकित्सा सुविधा से वंचित रखना.केन्द्र सरकार से पूर्व मे प्रदत्त रेल यात्रा सुविधा को बंद कर देने.आयकर के दायरे से पेशनरो को मुक्त रखने.8 वां वेतन आयोग के लाभ की स्पष्टता.छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश के पेशनरो के लिये बनाये गये अब्यवहारिक धारा 49 की प्रतिबधता को समाप्त करने जैसे कई ब्यवहारिक विषयो पर इस राष्ट्रीय मंच पर विचार कर आवश्यक निर्णय लिया जावेगा.

ग्राम पंचायत बम्हनी में लोधी समाज सामुदायिक भवन का भूमिपूजन एवं महतारी सदन का लोकार्पण संपन्न

पाटन (समय दर्शन)। जनपद पंचायत कवर्धा अंतर्गत ग्राम पंचायत बम्हनी में लोधी समाज सामुदायिक भवन के भूमिपूजन एवं महतारी सदन के लोकार्पण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं समाज के पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोधी समाज छत्तीसगढ़ के युवा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिंगौर ने की। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत कबीरधाम की अध्यक्ष ईश्वरी साहू एवं लोधी समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश संगठन मंत्री जीवन कौशिक उपस्थित रहे।

विशिष्ट अतिथियों में जनपद पंचायत कवर्धा की अध्यक्ष सुषमा गनपत बघेल, जिला लोधी समाज के अध्यक्ष संतोष कौशिक, अगेश्वर कौशिक (कुरहा), डेरहा कौशिक (दीवान), सुषमा धरम कौशिक (जनपद सदस्य) तथा ग्राम पंचायत बम्हनी के सरपंच चितरेखा-सुरेश कौशिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन जिला लोधी समाज कबीरधाम एवं समस्त ग्राम पंचायत परिवार बम्हनी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेश लोधी समाज के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पीलाराम कौशिक, प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश कौशिक, अधीन जेघल, रामफल कौशिक, आजू राम कौशिक, प्रदेश प्रचार सचिव श्रवण कौशिक, जिला महामंत्री संजू कौशिक, संगठन मंत्री राजेश कौशिक, जिला कोषाध्यक्ष रूपेश कौशिक, युवा जिला अध्यक्ष नरेंद्र कौशिक सहित यशवंत कौशिक, धीरज कौशिक, तुकेश कौशिक एवं बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज की एकजुटता, शिक्षा, सामाजिक उत्थान एवं सामुदायिक भवन के महत्व पर प्रकाश डाला। भूमिपूजन एवं लोकार्पण के साथ ही क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई गई।

सफाई के लिए फेंसिंग तार हटाने महापौर लिखेगी बी.एस.पी. को पत्र, पुलिस गस्त की मांग महापौर से

रिसाली (समय दर्शन)। शिवपारा स्टेशन मरोदा स्थित सुलभ शौचालय के आगे बीएसपी द्वारा लगाए फेंसिंग तार को हटाने महापौर शशि सिन्हा भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों को पत्र लिखेगी। फेंसिंग की वजह से सफाई कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। नगर पलिक निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा वार्ड 17 शिवपारा स्टेशन मरोदा पहुंची। भ्रमण के दौरान नागरिकों ने शिकायत की है कि सुलभ शौचालय नंदी चैक के आगे अतिक्रमण को रोकने इस्पात संयंत्र ने फेंसिंग तार का घेरा लगा दिया है। इस वजह से झाड़ियों और नाली में जमे मलबा की सफाई नहीं हो पा रहा है। गंदा पानी का निकासी नहीं हो रहा है। नागरिकों की समस्याओं पर महापौर शशि सिन्हा ने आश्वासन दी कि वे जल्द ही बीएसपी प्रबंधन को पत्र लिख फेंसिंग तार हटाने कहेंगी ताकि सफाई कार्य बाधित न हो। वहीं उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद गजेन्द्री कोठारी को भी इसी कार्य के लिए पृथक से पत्र लिखने कही। इस दौरान एमआईसी अनिल देशमुख, संजू नेताम, पार्षद गजेन्द्री कोठारी, रेखा देवी, उपअभियंता डिगेश्वरी चंद्राकर, राजस्व विभाग के प्रभारी अधिकारी योगेश सुरे, जल कार्य विभाग के गोपाल सिन्हा आदि उपस्थित थे।

ग्राम तरीघाट के लंबित विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम लवकेश ध्रुव को सौंपा ज्ञापन

पखवाड़े भर में काम नहीं हुआ तो किया जाएगा जनआंदोलन

पाटन (समय दर्शन)। तहसील पाटन के ग्राम तरीघाट के ग्रामीणों ने गांव में रुके एवं अधूरे पड़े विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग को लेकर एसडीएम पाटन लवकेश ध्रुव को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम तरीघाट, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख मांगें शामिल हैं—

सोलर सौर योजना के तहत पम्प हाउस निर्माण एवं पम्प स्थापना

तालाब भराई (सिंचाई) योजना के अंतर्गत पम्प लगाया जाना था, किंतु विभागीय लापरवाही के चलते पम्प अब तक गांव के ऑपरेटर के घर में रखा हुआ है और तालाब में फिट नहीं किया गया है। वर्तमान में नदी में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद तालाब में निस्तारी हेतु जल भराव नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने आगामी गर्मी को देखते हुए पम्प को तत्काल स्थापित कराने की मांग की है। नदी किनारे निर्माणाधीन तटबंध का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। इससे बाढ़ एवं कटाव की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने इसे शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की है। ग्राम में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा विश्राम गृह लंबे समय से अधूरा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह भवन सार्वजनिक उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत: इसे जल्द पूरा कराया जाए। ग्राम में निर्मित छह बिस्तर अस्पताल के जच्चा कक्ष के मुख्य द्वार पर अतिक्रमण होने से आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों ने तत्काल अतिक्रमण हटाने की मांग की है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रूप से संचालित हो सकें। वर्ष 2010-11 में पुरातत्व विभाग द्वारा ग्राम तरीघाट में की गई खुदाई में विभिन्न ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई थी। इन अवशेषों के संरक्षण के लिए ग्राम में संग्रहालय की स्थापना भी की गई, किंतु अब तक खुदाई में प्राप्त सामग्रियों को संग्रहालय में नहीं रखा गया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिलाई शपथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा बिलासपुर प्रेस क्लब बिलासपुर

बिलासपुर (समय दर्शन)। प्रेस क्लब बिलासपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि अरुण साव ने नई टीम को शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने की, विशेष अतिथियों के रूप में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, नगर निगम सभापति विनोद सोनी तथा नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में संपन्न चुनाव में अजीत मिश्रा प्रेस क्लब बिलासपुर के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उपाध्यक्ष पद पर विजय क्रांति तिवारी, सचिव संदीप परिहार, कोषाध्यक्ष किशोर कुमार सिंह, सहसचिव हरिशंकर गंगवानी तथा कार्यकारी सदस्य के रूप में कैलाश यादव चुने गए हैं।

मुख्य अतिथि एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नई टीम को बधाई देते हुए कहा कि कड़ी मेहनत और एकजुटता के साथ यह टीम बिलासपुर का नाम और ऊंचा करेगी। उन्होंने कहा कि बिलासपुर प्रेस क्लब से अनेक वरिष्ठ पत्रकार निकले हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बिलासपुर को पहचान बनाई है। नई टीम इस गौरव को और आगे बढ़ाएगी। उन्होंने पत्रकारिता को चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बताते हुए कहा कि इसमें निरंतर मेहनत, प्रतिबद्धता और निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। बड़ी संख्या में जुड़े नए पत्रकारों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने इसमें राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों को भी आमंत्रित करने का सुझाव दिया। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि बिरकोना स्थित पत्रकार कॉलोनी में सड़क निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। साथ ही प्रेस क्लब भवन के कायाकल्प का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने न्यायधानी की गरिमा के अनुरूप प्रेस क्लब को मजबूत बनाने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

अध्यक्षीय उद्बोधन में विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को माना गया है। मीडिया न केवल राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखती है, बल्कि बिलासपुर के हितों के लिए संघर्ष में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि प्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों पर राजधानी रायपुर में उच्च स्तरीय बैठकों में चर्चा कर निर्णय लिया जाना इसकी प्रभावशीलता का प्रमाण है विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि प्रेस क्लब केवल समाचार प्रकाशन तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय हितों की रक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभाती है।

बिलासपुर में रेलवे जोन और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रेस क्लब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विधायक सुशांत शुक्ला ने प्रेस क्लब की निष्पक्ष पत्रकारिता की सराहना करते हुए कहा कि बिलासपुर को उसका वाजिब हक दिलाने में मीडिया ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नव निर्वाचित प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री अजीत मिश्रा ने स्वागत भाषण दिया। उपाध्यक्ष श्री विजय क्रांति तिवारी ने आभार व्यक्त किया।

छत्तीसगढ़ मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने अद्भुत परियोजना का अवलोकन किया

सेवोक-रंगपो रेलवे परियोजना दिसंबर 2027 तक पूरी होगी

रायपुर। सिक्किम की धुंध से ढकी पहाड़ियों और गहरी घाटियों के बीच, स्टील की पटरियों पर एक क्रांति आकार ले रही है। जिसे कभी एक दुर्गम क्षेत्र माना जाता था, अब उसे महत्वाकांक्षी 'सेवोक-रंगपो' रेलवे परियोजना के साथ जोड़ा जा रहा है, जो न केवल कनेक्टिविटी, बल्कि भारत की पूर्वोत्तर सीमा के लिए वाणिज्य, गतिशीलता और एकीकरण के एक नए युग का संकेत दे रही है। 44.96 किमी लंबी सेवोक-रंगपो लाइन का काम प्रगति पर है और इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो सिक्किम को अपनी पहली रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

छत्तीसगढ़ से आए पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने सिक्किम के रंगपो में सेवोक-रंगपो परियोजना स्थल का दौरा किया। परियोजना के विवरण पर परियोजना के सलाहकार मोहिंदर सिंह ने प्रकाश डाला। उन्होंने सूचित किया कि

44.96 किमी लंबी सेवोक-रंगपो लाइन का कार्य प्रगति पर है और इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे सिक्किम को पहली रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना का लगभग 90त्न कार्य पूरा हो चुका है और भारत के पहले टनल स्टेशन 'तीस्ता बाजार' का काम लगभग पूरा होने वाला है। परियोजना के कुल 5 स्टेशन पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं। इस परियोजना की सबसे लंबी सुरंग लगभग 5300 मीटर और सबसे छोटी सुरंग 542 मीटर लंबी है। इस परियोजना की आधारशिला 30 अक्टूबर 2019 को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा रंगपो में और रेल मंत्री द्वारा सिवोक में रखी गई थी।

उप मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी के प्रतिमा का किया लोकार्पण

रायपुर। छत्रपति शिवाजी की 396 वें जन्म जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने किया। यह प्रतिमा कवर्धा शहर में छत्रपति शिवाजी चौक पर स्थापित की गई है। प्रतिमा के पार्श्व में किले की दीवार और आजू बाजू में तोपों की प्रतिकृति बनाई गई है। जो पूरे प्रतिमा को भव्यता प्रदान कर रही है।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा यह कवर्धा के लिए ऐतिहासिक दिन है जब अदम्य वीरता और साहस के प्रतीक छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा उनके जन्म जयंती के अवसर पर यहां स्थापित की जा रही है। छत्रपति शिवाजी का व्यक्तित्व हमारे समाज और युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणादायी रहा है कि कैसे उन्होंने मुगल आतंक को चुनौती दी और अपनी वीरता से एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर विदेशी ताकतों के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध का प्रतीक बना। यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ी को प्रेरणास्त्रोत के रूप में राष्ट्र प्रेम की सीख देगा।

प्रदेश में लाल आतंक के खात्मे पर उन्होंने कहा कि हम सशस्त्र नक्सलिज्म को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। आज हम बस्तर से लाल आतंक के समूल नाश करने में निर्णायक स्थिति में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में यह संकल्प लिया गया था जिसे पूर्ण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं।

कवर्धा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 146 करोड़ की लागत से भव्य भोरमदेव मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें मड़वा महल, छेरकी महल और रामचुंवा को भी शामिल किया गया है, यहां के सरोवर और मेला स्थल को भी संवारा जाएगा। इसी प्रकार बूढ़ा महादेव मंदिर के उन्नयन एवं नदी तट को संवारने का काम किया जाएगा। यहां कांवड़िया सदन का निर्माण भी होने जा रहा है।

विधायक दुर्ग ग्रामीण श्री ललित चंद्राकर ने कहा कि छत्रपति शिवाजी ने देश को एकजुट कर भारत को भारत बनाने में अपने प्राण न्यौछावर किया। उनका व्यक्तित्व आज इतने वर्षों बाद भी उतना ही प्रेरणादायी व अनुकरणीय है। उन्होंने पूरे समाज और पूरे देश को एक किया है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा की स्थापना शहर को न केवल भव्यता दे रहा है बल्कि युवाओं को हमारे अमर बलिदानी के योगदान की हमेशा याद दिलाएगा।

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में प्रो. मनोज दयाल ने संभाला कुलपति का पदभार

रायपुर। प्रतिष्ठित मीडिया शिक्षाविद प्रो. (डॉ.) मनोज दयाल ने आज कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति के रूप में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर रायपुर के संभागायुक्त महादेव कावरे ने कुलपति को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कुलपति प्रो. दयाल ने विश्वविद्यालय के प्रेरणास्रोत, अद्भुत संगठन शिल्पी और त्याग-सादगी की प्रतिमूर्ति कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर श्रद्धा-सुमन अर्पित कर प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने माननीय राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय परिवार के सभी

सदस्यों से परिचय प्राप्त किया। प्रो. दयाल ने ग्रंथालय में शोधार्थियों एवं पीजी विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनके शोध कार्यों की जानकारी ली। विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो संवाद 90.8 एफएम में उन्होंने शुभकामना संदेश रिकॉर्ड किया तथा टेलीविजन स्टूडियो और विभिन्न संकाय भवनों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से संवाद कर शैक्षणिक गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, प्राध्यापकगण, अधिकारी एवं कर्मचारियों ने नवागत कुलपति का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी, युवा बदलेंगे भारत का भविष्य - राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा

रायपुर। धमतरी स्थित बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज वार्षिक स्नेह सम्मेलन उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया गया है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य की निर्णायक भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास की आधारशिला है और आज का युवा नई तकनीकों का कुशल उपयोग कर स्वयं को ऊँचाइयों तक पहुंचा रहा है। एक सकारात्मक विचार जीवन की दिशा बदल सकता है। विचार ही सामान्य व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं।उन्होंने युवाओं से नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक सोच अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय

भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार घोषणाओं से अधिक कार्यों में विश्वास रखती है।

इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने विद्यार्थियों के आग्रह पर छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोकगायक लक्ष्मण मस्तुरिया का लोकप्रिय गीत प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए।

महापौर रामू रोहरा ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र में बीते दो वर्षों में लगभग 250 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 500 सीटर नालंदा परिसर, विधि विभाग भवन, हाईटेक बस स्टैंड, प्रमुख मार्गों का उन्नयन, ऑडिटोरियम, इंडोर स्टेडियम, विद्युत स्टेशन तथा सिहावा चौक से कोलियरी और रत्नाबांधा चौक से मुजगहन तक सड़क चौड़ीकरण जैसे कार्य शामिल हैं।

प्राचार्य श्री विनोद पाठक ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए महाविद्यालय की शैक्षणिक एवं खेल उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक रंजना साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष अंगिरा ध्रुव, नगर निगम सभापति कौशल्या देवांगन सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्राध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने किया डामरीकरण कार्य का भूमिपूजन कार्य तत्काल प्रारंभ कर पूर्ण गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने हेतु अधिकारियों को दिये निर्देश

गोपालपुर पुनर्वास गांव की वर्षो से जर्जर सड़कों का होगा जीर्णोद्धार व डामरीकरण

रायपुर। नगर पालिक निगम कोरबा के दर्री जोनांतर्गत जमनीपाली वार्ड के गोपालपुर पुनर्वास गांव की वर्षो से जर्जर पड़ी सड़कों का जीर्णोद्धार व डामरीकरण का कार्य कराया जाएगा, आज उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने उक्त महत्वपूर्ण कार्य का भूमिपूजन किया तथा कार्य को तत्काल प्रारंभ कराने, पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य करने तथा समयसीमा में कार्य को पूरा करने के निर्देश निगम के अधिकारियों व निर्माण कार्य एजेंसी को दिये।

प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री तथा कोरबा विधायक श्री लखनलाल देवांगन के प्रयासों से निगम के वार्ड क्र. 54 जमनीपाली अंतर्गत स्थित एनटीपीसी के पुनर्वास ग्राम गोपालपुर में बर्षो से जर्जर पड़ी सड़कों के जीर्णोद्धार व डामरीकरण हेतु एनटीपीसी के सीएसआर मद से 01 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, आवश्यक प्रक्रिया के पश्चात अब उक्त महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, आज उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत की अध्यक्षता में उक्त महत्वपूर्ण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया गया।

पुनर्वास ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करें प्रतिष्ठान - इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने एनटीपीसी सहित अन्य सार्वजनिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों का आव्हान करते हुए कहा है कि वे अपने पुनर्वास ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करें, पुनर्वास ग्रामों की समस्याओं को पूरी गंभीरता से लें तथा उनका समय-समय पर त्वरित निराकरण करायें। उन्होने कहा कि प्रतिष्ठानों का प्रथम दायित्व बनता है कि वे पुनर्वास ग्रामों के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील रहें तथा इन ग्रामों के विकास एवं उन्हें आदर्श स्वरूप में विकसित करने की दिशा में पूरी इच्छाशक्ति के साथ कार्य करें। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने आगे कहा कि वर्तमान में निगम द्वारा वार्ड क्र. 54 जमनीपाली वार्ड में 53 लाख रूपये के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा 02 करोड 61 लाख रूपये के कार्य वार्ड की विभिन्न बस्तियों में प्रगति में हैं, वहीं 58 लाख रूपये के नये कार्य भी इस वार्ड हेतु स्वीकृत किये गये हैं। उन्होने कहा कि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम के सभी वार्डो में वहाँ के नागरिकों की आवश्यकता व मांग के अनुसार व्यापक स्तर पर विकास कार्य वर्तमान में कराये जा रहे हैं तथा बिना किसी भेदभाव के कार्य हो रहे हैं। उन्होने आगे कहा कि निगम क्षेत्र में विगत 02 वर्षो के दौरान 865 करोड़ रूपये के विकास कार्य विभिन्न मदों के अंतर्गत स्वीकृत कराये जा चुके हैं तथा यह प्रयास किया जा रहा है कि विकास कार्यो हेतु किसी भी प्रकार की धनराशि की कमी न होने पाये।

लगातार जारी रहेगी विकास कार्यो की गति - इस मौके पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि नगर निगम कोरबा क्षेत्र में विकास की यह गति लगातार जारी रहेगी तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरूण साव एवं उद्योग मंत्री तथा कोरबा विधायक श्री लखनलाल देवांगन के निरंतर मार्गदर्शन में कोरबा का सर्वांगीण विकास होकर रहेगा।

संक्षिप्त समाचार

न बारिश न ठंड फिर विजिबिलिटी हुई कम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल पूरी तरह स्थिर बना हुआ है और अगले कुछ दिनों तक इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में अगले 7 दिनों और अधिकतम तापमान में 5 दिनों तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। राजनांदगांव में 34 डिग्री के साथ सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर 9 डिग्री के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। प्रदेशभर में मौसम शुष्क है और कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई है। राजधानी रायपुर में 19 फरवरी को सुबह हल्की धुंध छाए रहने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम पूरी तरह स्थिर बना हुआ है। न तो बारिश के आसार हैं और न ही तापमान में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक प्रदेश का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। यानी फिलहाल न गर्मी बढ़ने वाली है और न ही ठंड अचानक से वापसी करेगी।

तापमान में रहेगा संतुलन- मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। वहीं अधिकतम तापमान भी अगले 5 दिनों तक लगभग स्थिर रहेगा, इसका मतलब साफ है कि अभी मौसम सामान्य रहेगा और लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। दिन में हल्की गर्मी और रात में हल्की ठंड का असर बना रह सकता है, खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ के इलाकों में।

विधायक सोनी ने महाविद्यालय में 10 लाख के निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन

रायपुर :- विधायक श्री सोनी ने आज शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं छत पर डोम निर्माण (लागत राशि 10 लाख) के लिए भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। विधायक श्री सोनी ने कहा कि डोम निर्माण के बाद महाविद्यालय की छत पर बैडमिंटन सहित अन्य इनडोर खेलों का आयोजन किया जा सकेगा तथा विभिन्न शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अधिक सुविधा के साथ संपन्न होंगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी प्रदेश या देश के उज्ज्वल भविष्य में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। महाविद्यालयों में अध्ययनरत युवा ही आने वाले समय में राष्ट्र की उन्नति में सहभागी बनते हैं, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। अंत में उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए पुनः सभी को शुभकामनाएँ दीं।

फतेहशाह मार्केट में गुंडागर्दी करने वाला बदमाश गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर कमिश्नरेट में डीसीपी सेंट्रल ज़ोन के निर्देशन में गुंडा बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 18.02.2026 को थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत फतेहशाह मार्केट में गुंडा बदमाश वसीम खान उर्फ मम्मा, पिता मोह. हाफिज खान, निवासी चांदनी चौक, नेहरू नगर द्वारा नशा करने के लिए दुकानदारों से जबरन पैसे की मांग की गई। पैसे नहीं देने पर आरोपी द्वारा दुकानदारों के साथ गाली-गलौच एवं मारपीट कर क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास किया गया। प्रकरण में अविलंब अपराध पंजीबद्ध करते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना सिटी कोतवाली, रायपुर में अपराध क्रमांक 68/26 धारा 296, 119(1), 115(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया।

टेक सॉल्यूशंस एक स्केलेबल यूनिफाइड एआई प्लेटफॉर्म विकसित करेगा, जो 370 बिलियन डॉलर के राष्ट्रीय हेल्थकेयर इकोसिस्टम में परिवर्तन लाने के इंडियाएआई मिशन के अनुरूप होगा

चेन्नई : नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अवसर पर, टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड ने आज एक व्यापक यूनिफाइड एआई प्लेटफॉर्म विकसित करने की अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान की घोषणा की। हेल्थकेयर इकोसिस्टम में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया यह प्लेटफॉर्म एक वन-स्टॉप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के रूप में कार्य करेगा, जो अस्पतालों, डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज़, क्लिनिकल ट्रायल संगठनों और क्लिनिक्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों को सहज रूप से अपनाने और उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। यह पहल टेक सॉल्यूशंस के विकास में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो देश के विकास के लिए एआई को एक महत्वपूर्ण विकास उपकरण के रूप में अपनाने के भारत सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। भारत 370 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हेल्थकेयर सेक्टर और 197 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रिवेंटिव हेल्थकेयर अवसर को अनलॉक करने पर केंद्रित है। यह प्लेटफॉर्म अपनी आधुनिक टेक्नोलोजी को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाकर समिट की मुख्य थीम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय (सभी का कल्याण और सभी की खुशी) को प्रतिबिंबित करता है।

हेल्थकेयर वर्कर्स के लिए एआई: यह प्लेटफॉर्म स्केलेबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और हेल्थकेयर डिलीवरी में मौजूद अंतर को दूर करने के सरकार के लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है तथा एक व्यापक हेल्थकेयर एआई मार्केटप्लेस और इंटीग्रेशन लेयर के रूप में कार्य करेगा। यह शहरी केंद्रों और वंचित समुदायों दोनों में हेल्थकेयर प्रदाताओं को एक सिंगल यूनिफाइड इंटीग्रेशन के माध्यम से एआई-संचालित एप्लिकेशनों की व्यापक रेंज को आसानी से एक्सेस, डिप्लॉय और मैनेज करने के लिए सशक्त बनाता है।

संपादकीय

अमेरिका से ट्रेड डील

पीयूष गोयल के मुताबिक ट्रेड डील में रूसी तेल का मुद्दा नहीं है। इसलिए इस पर विदेश मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए। विदेश मंत्री गोयल से पूछने की सलाह दे चुके हैँ। प्रधानमंत्री से तो स्पष्टीकरण की अपेक्षा ही नहीं है। अमेरिका से ट्रेड डील में रूसी तेल के मुद्दे को शामिल करने से भारत को आर्थिक के साथ-साथ प्रतिष्ठा का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री इसकी जवाबदेही एक दूसरे पर टालने की जुगत में दिखे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक उन्होंने जो डील की, उसमें यह मुद्दा नहीं है, इसलिए इस बारे में विदेश मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए। विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस बारे में गोयल से पूछने की सलाह दे चुके हैँ। प्रधानमंत्री चूंकि असहज करने वाले सवालों पर कभी कुछ नहीं बोलते, इसलिए उनसे कोई स्पष्टीकरण मिलने की संभावना वैसे भी नहीं है। ये सच है कि ट्रेड डील से संबंधित साझा बयान में इस मसले का जिक्र नहीं है। लेकिन साझा बयान जारी होने के साथ ही ह्वाइट हाउस ने अलग विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भारत रूसी तेल की खरीदारी रोकने पर राजी हुआ है। यह भी बताया कि भारत कहीं चोरी-छिपे तेल ना खरीद ले, इसकी निगरानी अमेरिका के तीन मंत्री करेंगे। भारत सरकार के किसी मंत्री या अधिकारी ने इस अमेरिकी एलान का खंडन नहीं किया। उलटे मंत्री इसकी जवाबदेही दूसरे पर टालते दिखे हैं। इसलिए इसे ट्रेड डील का हिस्सा मान लिया गया है और बाजार में उसका असर दिखने लगा है। पहली मार गुजरात के वाडीनगर में स्थित नायरा रिफाइनरी पर पड़ती दिखी है। रूस की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी रोसनेफ्त की इसमें सबसे बड़ी शेयरहोल्डिंग है। इसमें अधिकतर रूस से आए कच्चे तेल का शोधन किया जाता है। लेकिन अब अमेरिका से ट्रेड डील के बाद इस रिफाइनरी का चलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो ये चर्चा शुरू हो गई है कि रोसनेफ्त के शेयर खरीद कर कोई भारतीय कंपनी इसकी मालिक बनेगी और फिर वह अन्य स्रोतों से आए तेल का शोधन करेगी। अनुमान है कि यह तेल अधिकांशत: अमेरिका से आएगा। मगर यह महंगा सौदा है। अमेरिका से तेल ऊंचे भाव में मिलेगा। परिवहन खर्च पर बड़ी कीमत चुकानी होगी। उधर अमेरिकी दबाव में आने के कारण अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को पहुंची हानि अलग है। इसीलिए इसकी जवाबदेही पर मुंह छिपाने की जरूरत पड़ी है।

क्या शबाना महमूद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनेंगी?

डॉ. सुधीर सक्सेना

वह सुदर्शना है। सुशिक्षिता है। युवा और अनुभवी हैं। तत्पर और प्रत्युत्पन्नमति हैं। संसद और बाहर वह मुखर है। कलुष के बेदब दौर में उनकी छवि बेदाग और उजली है। इतनी खूबियों से सुसज्ज शबाना महमूद इन दिनों सुर्खियों में हैं। संप्रति वह ब्रिटेन की सेक्रेट्री फार द होम यानि गृहमंत्री है। एप्सटीन फाइल्स के जेरे-बहस दौर में इस आशय की अटकलों का सब्जा दरो-दीवार और मुंडेरों पर उग आया है कि क्या वह ब्रिटेन की प्रधानमंत्री होंगी। फिलहाल उनके और प्रधानमंत्री पद के दरम्यान एक सोपान का फासला है। यदि वह प्रधानमंत्री बनती हैं, तो वह एशियाई मूल की दूसरी और मुस्लिम संप्रदाय की पहली महिला होंगी। गौरतलब है कि भारतीय मूल के ऋषि सूनक इसके पूर्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके है, जबकि शबाना पाकिस्तानी मूल की नेत्री है। लोकतंत्र के जनक ब्रिटेन में इन दिनों कुख्यात एप्सटीन फाइल्स को लेकर बावेला मचा हुआ है। कई राजनेता पद त्याग को बाध्य हुये हैं। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यदि दबाव अधिक बढ़ा तो मजबूरन उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। इस कयास के मद्देनजर शबाना महमूद के पीएम बनने की संभावना प्रबल है। 45 वर्षीया शबाना सत्तारुढ़ ब्रिटिश लेबर पार्टी की सदस्या और बैरिस्टर हैं। वह पहले पहल सन 2010 में मई के आमचुनाव में बर्मिंघम लेडीवुड से एमपी चुनी गयी थीं। तदंतर वह चुनावों में लगातार विजयी हुई। जीत की हैटट्रिक बना चुकी शबाना ब्रिटिश लेबर पार्टी की अग्रणी नेताओं में शुमार हैं। सन 2024-25 में सेकेट्री फार जस्टिस यानि न्यायमंत्री रहने के बाद गत वर्ष उन्हें गृह जैसा महत्वपूर्ण महकमा सौंपा गया। 17 सितंबर, सन 1980 को बर्मिंघम में जनमी शबाना के परिवार की जड़े पाकअधिकृत काशमीर में मीरपुर में है। माँ जुनेदा और पिता महमूद अहमद की संतान शबाना के दो भाई और एक बहन है। अनमें एक उनका जुड़वा भाई है। सन 1981 से 1986 तक वह परिवार के साथ सऊदी अरब तैफ में रहीं जहां उनके पिता सिविल इंजीनियर थे। उसके बाद परिवार बर्मिंघम चला आया। पिता जहाँ लेबर गर्टी से जुड़ गये, वहीं मां स्वयं की सुविधा-शॉप का संचालन करने लगीं 11वीं कक्षा में अनुतीर्ण रहने पर वह स्माल हीथ स्कूल और किंग एडवर्ड षष्टम कैंप हिल स्कूल में पढ़ीं। अंतत: उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंतर्गत लिंकन कॉलेज से कानून में उपाधि हासिल की। पूर्व पीएम ऋषि सूनक कॉलेज में उनसे एक दर्जा आगे थे और शबाना जूनियर कॉमन रूम के चुनाव में ऋषि ने उन्हें वोट देने का वायदा किया था। युवा शबाना बर्मिंघम में पिता के राजनीतिक कार्यों में हाथ तो बंटाती थीं, अलबत्ता उनकी ख्वाहिश थी कि वह बैरिस्टर बने। उनकी यह ख्वाहिश पूरी हुई। सन 2010 में जब निवर्तमान सांसद क्लेयर शार्ट ने बर्मिंघम से चुनाव लड़ने की अनिच्छा व्यक्त की तो शबाना ने दावेदारी की होड़ में याई मॉर्स्क्रटो को पीछे छोड़ दिया। इस द्वन्द ने इलाके में जातिीय धड़ेवाजी को को बढ़ावा दिया, वह फिलिस्तीन समर्थक और इस्रायली उत्पादों के बहिष्कार की हिमायती नेत्री के तौर पर उभरीं। विवाद होने पर उन्होंने सतर्कतापूर्वक अपने पाँव पीछे खींच लिये, लेकिन इसने उनकी छवि जियोनिज्म (यहूदीवाद) विरोध की बना दी। वह इस्लाम में गहरी आस्था के लिये भी जानी गयीं और उन्होंने इसे कभी छुपाया नहीं। शबाना, रोशनआरा अली और यास्मीन कुरैशी की तिकड़ी ने बीते दशक में खासी शोहरत कमाई। लेबर नेता जेरेमी कार्बिन्स से मतभेदो को उन्होंने कभी छिपाया नहीं और साहसपूर्वक दायित्व संभालने की पेशकशों को ठुकरा दिया। बहरहाल, सितंबर 2023 में कीर स्टार्मर ने उन्हें शैडो सेक्रेट्री बनाया।

असमानताओं पर प्रहार, समानता का विस्तार : एक सार्थक पुकार

ललित गर्ग

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज के समय में केवल असमानताओं पर प्रहार एवं समानता के विस्तार की एक सार्थक पुकार का अंतरराष्ट्रीय आयोजन ही नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना का आह्वान है। वर्ष 2026 में यह दिवस विशेष महत्व ग्रहण कर रहा है, क्योंकि विश्व तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, तकनीकी संक्रमण, जलवायु संकट, राजनीतिक ध्रूवीकरण और सामाजिक असमानताओं के बीच नई संतुलित व्यवस्था की तलाश में है। इस वर्ष की थीम समावेश को सशक्त बनाना: सामाजिक न्याय के लिए अंतर को पाटना हमें यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह समावेशी हो और समावेशन तभी प्रभावी है जब वह न्यायपूर्ण हो। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल अवसरों की समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक व्यवस्था की स्थापना का आग्रह करता है जिसमें संसाधनों, अधिकारों और गरिमा का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हो। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की समान उपलब्धता नहीं मिलती, तब तक प्रगति अधूरी है। 2026 की थीम विशेष रूप से उन समुदायों की भागीदारी पर बल देती है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं- चाहे वे आर्थिक रूप से वंचित हों, सामाजिक रूप से उपेक्षित हों या राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व से दूर हों। समावेशन का सशक्तिकरण केवल नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का अधिकार है।

आज वैश्विक स्तर पर असमानताओं की खाई कई रूपों में दिखाई देती है। एक ओर तकनीकी क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, तो दूसरी ओर पारंपरिक श्रम-आधारित रोजगार असुरक्षित होते जा रहे हैं। डिजिटल विभाजन नई सामाजिक दूरी का कारण बन रहा है। ग्रामीण और शहरी, विकसित और विकासशील, पुरुष और महिला, सक्षम और दिव्यांग-इन सबके बीच संसाधनों की असमान पहुंच सामाजिक तनाव को जन्म देती है। ऐसे समय में सामाजिक न्याय का अर्थ है इन अंतरों को पहचानना और उन्हें पाटने के लिए लक्षित, संवेदनशील और पारदर्शी नीतियों का निर्माण करना। सम्मानजनक कार्य की अवधारणा भी

सामाजिक न्याय के केंद्र में है। केवल रोजगार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसा कार्य-संस्कृति बनाना आवश्यक है जिसमें उचित वेतन, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियां और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। आर्थिक विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह मानव गरिमा के साथ जुड़ा हो। यदि विकास केवल आंकड़ों में सीमित रह जाए और आम नागरिक के जीवन में राहत न ला सके, तो वह विकास नहीं, केवल विस्तार है।

मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र इस युग की अनिवार्यता बन चुका है। कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि संकट किसी भी समाज को अचानक अस्थिर कर सकता है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धजन, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक-इन सभी के लिए संरक्षित ढांचा ही न्यायपूर्ण समाज की नींव है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में सामाजिक न्याय का विचार ऐतिहासिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। आज भी सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक पूर्वाग्रहों, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय असंतुलन और सांस्कृतिक असमानताओं से भी जुड़ा है।समकालीन भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और नशा-पीड़ित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि सामाजिक न्याय विभाजन की राजनीति नहीं, बल्कि समावेशन की नीति के माध्यम से स्थापित हो। संतुष्टिकरण बनाम तुष्टिकरण की अवधारणा इसी दिशा में एक वैचारिक संकेत है, जो समाज को जोड़ने की बात करती है। फिर भी चुनौतियां शेष हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ती जीवन-यापन लागत आम नागरिक के लिए वास्तविक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि जनसंतोष और जनकल्याण सुनिश्चित करना है। यदि नागरिक स्वयं को असुरक्षित, असमान या उपेक्षित अनुभव करें, तो सामाजिक न्याय का आदर्श खोखला प्रतीत होने लगता है।

आज आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व के रूप में देखा जाए। हमने आचरण की पवित्रता एवं पारदर्शिता की बजाय कदाचरण एवं अनैतिकता की कालिमा का लोकतंत्र बना रखा है। ऐसा लगता है कि धनतंत्र एवं सत्तातंत्र ने जनतंत्र को बंदी बना रखा है। हमारी न्याय-व्यवस्था कितनी भी निष्पक्ष, भव्य और प्रभावी हो, फ्रांसिस बेकन ने ठीक कहा था कि 'यह ऐसी न्याय-व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की यंत्रणा के लिये दस अपराधी दोषमुक्त और रिहा हो सकते हैं।' रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था कि 'मनुष्य का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है।' लेकिन हमारे देश के कानून एवं शासन व्यवस्था को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता, आम आदमी सजा का जीवन जीने को विवश है। सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक एकता भंग नहीं की जा सकती। शासन और प्रशासन की प्रत्येक नीति का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण होना चाहिए। यदि शक्ति के स्रोत जनहित में प्रयुक्त न हों, तो वे असंतोष और अविश्वास को जन्म देते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। क्या हमारा लोकतंत्र समानता का लोकतंत्र है या विभेद का? क्या हमारी स्वतंत्रता सबके लिए समान अवसर लेकर आई है या केवल कुछ वर्गों तक सीमित है? क्या हमारी नीतियां पारदर्शिता और नैतिकता पर आधारित हैं या वे जटिलता और असमानता को बढ़ा रही हैं? इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से खोजना ही इस दिवस की सार्थकता है।

सामाजिक न्याय केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के भेद से ऊपर उठकर यदि नागरिक परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, तो सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ किया जा सकता है। शिक्षा संस्थान, नागरिक संगठन, धार्मिक और सांस्कृतिक मंच-सभी को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा और डिजिटल नवाचार नए अवसर प्रदान कर रहे हैं, वहीं यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन अवसरों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। अन्यथा विकास की गाड़ी कुछ लोगों को आगे ले जाएगी और शेष को पीछे छोड़ देगी। समावेशन का सशक्तिकरण इसी असंतुलन को रोकने का प्रयास है। प्रतिदिन कोई न कोई कारण महंगाई को बढ़ाकर हम सबको और धक्का लगा जाता है और कोई न कोई टैक्स, अधिभार हमारी आय को और संकुचित कर जाता है। जानलेवा प्रदूषण ने लोगों की सांसों को बाधित कर दिया, लेकिन हम किसी सम्यक् समाधान की बजाय नये नियम एवं कानून थोप कर जीवन को अधिक जटिल बना रहे हैं। सामाजिक न्याय व्यवस्था तभी सार्थक है जब आम जनता निष्कंटक एवं समस्यामुक्त समानता का जीवन जी सके।

2026 का यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि न्याय और विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग सामाजिक न्याय से होकर ही गुजरता है। यदि समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान, सुरक्षा और अवसर के साथ जीवन जी सके, तभी हम कह सकेंगे कि हमने सामाजिक न्याय के आदर्श को साकार किया है। इस तरह सामाजिक न्याय केवल नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि चेतना का प्रश्न है। यह हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों में परिलक्षित होना चाहिए। जब नागरिक और शासन दोनों मिलकर समानता, गरिमा और अवसर की संस्कृति का निर्माण करेंगे, तभी विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होगी। समावेश को सशक्त बनाकर और असमानताओं की खाई को पाटकर ही हम एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, अधिक मानवीय और अधिक स्थायी हो।

शी-बॉक्स पोर्टल: कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा का डिजिटल कवच

सावित्री ठाकुर

भारत जब 2047 में अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर है, तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने महिला-नेतृत्वित विकास को राष्ट्रीय प्रगति का केंद्र बिंदु बनाया है। महिलाओं की समावेशी आर्थिक वृद्धि में निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हुए सरकार ने ऐसा सुरक्षित, सम्मानजनक और संवेदनशील कार्य वातावरण तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे महिलाएं आत्मविश्वास के साथ कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इसी दिशा में कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में कार्य करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते एक दशक में महिला सशक्तिकरण को केवल एक नारा नहीं, बल्कि नीति, संरचना और प्रभावी क्रियान्वयन का विषय बनाया है। नारी शक्ति को राष्ट्र की उन्नति का आधार मानते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यापक संस्थागत सुधार किए गए हैं। इसी दूरदर्शी दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक उदाहरण है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया शी-बॉक्स पोर्टल, जो कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और न्याय तक सहज पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त डिजिटल मंच के रूप में उभरा है। आज भारत में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी लगातार बढ़ रही है। महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 23.3त्न से बढ़कर 2023-24 में 41.7त्न हो गई। सरकारी और निजी क्षेत्रों के साथ-साथ स्टार्टअप्स, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और असंगठित क्षेत्रों में भी महिलाएँ बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि कार्यस्थल सुरक्षित, सम्मानजनक और भय-मुक्त हों। कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश अधिनियम) इसी उद्देश्य से बनाया गया था। मोदी सरकार ने कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डिजिटल गवर्नेंस के तहत शी-बॉक्स पोर्टल को 29 अगस्त 2024 को तकनीकी सुधारों के साथ पुन: लॉन्च किया, जिससे यह अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और पारदर्शी बन सके।

यह पोर्टल देशभर में गठित आंतरिक समितियों और स्थानीय समितियों से संबंधित सूचनाओं का एक केंद्रीकृत भंडार प्रदान करता है।

शी-बॉक्स पोर्टल का उन्नत संस्करण महिलाओं को सीधे संबंधित आईसी या एलसी के पास शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है। इससे शिकायत प्रक्रिया में होने वाली देरी और अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप में कमी आती है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मंच सरकारी या निजी, संगठित या असंगठित - हर क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए समान रूप से सुलभ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार की महिला सुरक्षा की नीति किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि समावेशी है। प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया विज़न के अनुरूप, शी-बॉक्स महिलाओं को सुरक्षित, सरल और गोपनीय तरीके से शिकायत दर्ज करने और उसकी प्रगति ट्रैक करने की सुविधा देता है। पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायत सीधे संबंधित कार्यस्थल की आंतरिक समिति या जिले की स्थानीय समिति तक पहुँचती है। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि आंतरिक समिति की अध्यक्ष के अलावा कोई अन्य व्यक्ति शिकायत का विवरण नहीं देख सकता, जिससे पीड़िता की पहचान सुरक्षित रहती है। पॉश अधिनियम के तहत सरकार का दायित्व है कि वह शिकायतों से संबंधित आंकड़ों का संधारण और निगरानी करे। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी शिकायत की जाँच के लिए 90 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है, जिसका पालन सुनिश्चित करने में शी-बॉक्स पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समयबद्ध निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा डैशबोर्ड अलर्ट, ईमेल और मेसेज के माध्यम से नियमित रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। यह सक्रिय प्रणाली मोदी सरकार की उत्तरदायित्व और परिणाम आधारित शासन की सोच को दर्शाती है।

शी-बॉक्स की प्रभावशीलता में नोडल अधिकारियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कार्यस्थल पर नियुक्त नोडल अधिकारी, नियोक्ता, आंतरिक/स्थानीय समिति और शिकायतकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि शिकायतें केवल दर्ज न हों, बल्कि उन पर समय पर और नियमानुसार कार्रवाई भी हो। महिला-केंद्रित नीतियों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज देश में 10 करोड़ से अधिक महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, और लखपति दीदी जैसी पहल के माध्यम से लाखों महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। वहीं नमो ड्रोन दीदी जैसी अभिनव योजनाएँ महिलाओं को आधुनिक तकनीक, कृषि सेवाओं और उद्यमिता से जोड़ते हुए उन्हें नए और औपचारिक कार्यक्षेत्रों में प्रवेश का अवसर दे रही हैं। ऐसे में जब बड़ी संख्या में महिलाएँ पहली बार संगठित और औपचारिक कार्यस्थलों का हिस्सा बन रही हैं, शी-बॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म उन्हें यह भरोसा देते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है - न केवल कानून बनाकर, बल्कि उसे ज़मीन पर प्रभावी और जवाबदेह ढंग से लागू करके।

बहुभाषी समर्थन, रीयल-टाइम ट्रैकिंग और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से शी-बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को केवल एक कानूनी प्रावधान तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे एक व्यवस्थित, भरोसेमंद और जवाबदेह संस्थागत ढांचे में परिवर्तित करता है।

शराबबंदी का वादा तो भूपेश बघेल ने किया था

सुनील दास

राजनीति में सच और झूठ अपनी सुविधा के अनुसार कहा जाता है।राजनीतिक दलों को झूठ कहने में राजनीतिक फायदा होता हो तो वह राजनीतिक झूठ कहने में कोई संकोच नहीं करते हैं।सच कहने से राजनीतिक नुकसान होता है तो वह सच नहीं कहते हैं।छत्तीसगढ़ में सत्ता में भाजपा है और विपक्ष में कांग्रेस है तो वह भाजपा को याद दिलाती है कि वह तो शराबबंदी की बात किया करती थी आज सत्ता में है तो वह शराबबंदी करती क्यों नही है।शराब से कमाई क्यों कर रही हैं, नई शराब दुकाने क्यों खोलने की बात कर रही है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि शराबबंदी की बात करने वाली भाजपा आज शराब खपत बढ़ाने में लगी है। इसके लिए शराब नीति बदलती है, इसके लिए अंग्रेजी शराब दुकान में देशी व देशी शराब दुकानों में अंग्रेजी शराब बेचने का निर्णय किया जा रहा है। पिछले साल 67 शराब दुकान खोली गईं थी, इस साल फिर 35 दुकान खोली जाने वाली हैं।

ऐसा होता रहता है जो विपक्ष में होता है वह सत्तारूढ़ दल को याद दिलाता रहता है कि कभी उसने क्या वादा किया था।

सरकार वह वादा पूरा नहीं करती है तो उसे बार बार याद दिलाया जाता है कि आपने चुनाव में महिलाओं से वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो राज्य में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी।सरकार बनने के बाद वह अपने वादे से मुकर गए और कहने लगे कि साल 2018 में महिलाओं का दवाब था कि प्रदेश में शराबबंदी हो।हम उनकी सभा में थे हमने भी घोषणा कर दी। इसके अलावा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी शराबबंदी की मांग होती रही।यह बातें सीएम भूपेश बघेल ने राजधानी के रायपुर के प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विवि शांति सरोवर में नशामुक्ति अभियान की शुरुआत करते कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि सीएम होने के नाते वह आज ही शराब दुकान बंद करा सकते हैं लेकिन क्या यह समस्या का समाधान है।यानी वह भूपेश बघेल जो महिलाओं का वोट लेने के लिए शराबबंदी का वादा करते हैं, सरकार बनने के बाद लगता है कि यह तो समस्या का समाधान नहीं है। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने अपने आपको नशे के खिलाफ बताते हुए लोगों का ध्यान शराबबंदी से हटाने के लिए यह कहना शुरू किया कि शराब से ज्यादा खतरनाक तो सूखा नशा है।शराब तो नशे का ही हिस्सा है।अगर सभी नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा तो माहौल बनेगा।इससे शराबबंदी भी हो सकती है और नशामुक्ति भी हो सकती है।नशामुक्ति में तो शराब,गांजा,सिगरेट,तंबाकू सब आते हैं।इसलिए सीएम बघेल ने राज्य शराबबंदी के वादे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नशामुक्ति का अभियान चलाने को कहा था। एक तरफ उनके राज में नशामुक्ति अभियान चलाने की बातें होती रही और दूसरी तरफ हजारों करोड़ का शराब घोटाला होता रहा यानी एक तरफलोगों को नशामुक्ति की बातें की जा रही थी और दूसरी तरफहजारों करोड़ रुपए की अवैध शराब बिक्री भी की जाती रही और उसी कांग्रेस पार्टी के लोग आज कह रहे हैं कि भाजपा शराब की खपत बढ़ा रही है। शराब से ज्यादा से ज्यादा कमाई कर रही है।

जहां तक शराब से कमाई की बात है तो ऐसी कोई सरकार आज तक किसी राजनीतिक दल की नहीं हुई है जिसने राज्य की शराब से होने वाली कमाई कम करने की कोशिश की है। कांग्रेस 2018 से 2023 तक सत्ता में रही।क्या उसने शराब से होने वाली कमाई कम करने का कोई प्रयास किया। उसने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया बल्कि उसने वादा तो शराबबंदी का किया लेकिन शराब से कमाई तो उसने भी बढा़ने की पूरी कोशिश की। आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि कांग्रेस के समय भी शराब से होने वाली आय बढ़ी थी।20-21 में शराब से राजस्व 4639 करोड़ तो 22-23 में बढ़कर 6783 करोड़ रुपए हो गया था। माना जा सकता है कि हर सरकार की कोशिश रहती है कि शराब से कमाई हर साल एक दो हजार करोड़ बढे ताकि सरकार को जो खर्च बढ़ता है,उसकी भरपाई की जा सके। जो सब सरकारें करती है, वही साय सरकार भी कर रही है। वह भी अपने खर्च के लिए शराब से कमाई कर रही है। इसलिए इसे तो गलत नहीं कहा जा सकता। गलत को तब होता जब कोई राजनीतिक दल एक तरफचुनाव घोषणापत्र में वादा करता है उनकी सरकार बनेगी तो वह शराबबंदी करेंगे और सरकार बनने के बाद वह शराबबंदी की जगह शराब से ज्यादा कमाई भी करता है और शराब घोटाला भी होने देता है। यानी वैध रूप से तो वह शराब की खपत बढ़ाता ही है, अवैध रूप से भी शराब की खपत को बढ़ाता है ताकि उसे वैध के साथ अवैध कमाई भी होती रहे। वैध कमाई से सरकार का खर्च चलता रहे और अवैध कमाई से पार्टी का काम चलता रहे। साय सरकार के समय शराब से वैध कमाई हो रही है तो यह कोई अपराध नहीं है,बुरी बात नहीं है क्योंकि सभी सरकारे शराब से वैध कमाई करती है और उसका उपयोग जनता के भले के लिए किया जाता है। साय सरकार ने कभी शराबबंदी का वादा नहीं किया यह जनता जानती है इसलिए कोई कितना भी कहे कि शराबबंदी की बात करनेवाली भाजपा शराबबंदी नहीं कर रही है तो कोई विश्वास नहीं करने वाला है।

मुंगेली जिले के 41 विद्यालयों के लिए व्यावसायिक शिक्षा स्वीकृत 82 लाख की पीएफएमएस राशि तीन माह से लंबित, शिक्षा व्यवस्था प्रभावित

कलेक्टर जनदर्शन में लिखित शिकायत पर निष्पक्ष जांच टीम गठित नहीं पतंगबाजी कि तर्ज पर कलेक्टर जनदर्शन पोर्टल पर जवाब प्रतिवेदन पत्र अपलोड कर किया निराकृत तो वहीं शिकायतकर्ता असंतुष्ट

मुंगेली (समय दर्शन)। व्यावसायिक शिक्षा समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत मुंगेली जिले के 41 शासकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालन हेतु भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रति विद्यालय ?2 लाख की दर से कुल ?82 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, किंतु राज्य परियोजना कार्यालय से स्वीकृति मिलने के दो माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आज दिनांक तक जिले में **PFMS** प्रणाली के माध्यम से उक्त राशि की लिमिट जारी नहीं की गई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार **PFMS** के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को सीधे वित्तीय लिमिट जारी किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है, जिससे विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। किंतु राशि जारी नहीं होने के कारण विद्यालय स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं तथा विद्यार्थियों को निर्धारित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में जिला कलेक्टर जनदर्शन, मुंगेली में लिखित शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि जिला स्तर पर **PFMS** प्रक्रिया में गंभीर प्रशासनिक उदासीनता निष्क्रियता एवं अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, जिससे शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है।शिकायत में मांग की गई है कि **PFMS** लिमिट जारी करने में विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की पहचान कर जिला स्तर पर स्वतंत्र जांच कराई जाए, संबंधित फाइलों की जांच हो तथा दोषी पाए जाने पर विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी मांग की गई है कि स्वीकृत 82 लाख की राशि की लिमिट तत्काल जारी की जाए, ताकि व्यावसायिक शिक्षा का संचालन बाधित न हो।इस विषय में शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि शीघ्र प्रभावी कार्यवाही नहीं होती है।तो प्रकरण को विभागीय उच्च कार्यालय एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।यह मामला सीधे तौर पर विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य से जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वित्तीय स्वीकृति समय पर जारी नहीं की जाती है, तो केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाता, जिससे शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में कितनी शीघ्रता से संज्ञान लेकर ठोस कदम उठाता है और कब तक 41 विद्यालयों को स्वीकृत 82 लाख की **PFMS** राशि जारी हो पाती है।

मुंगेली के 41 विद्यालयों को 82 लाख की पीएमएफएस राशि शीघ्र जारी होगी जिला शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी

व्यावसायिक शिक्षा समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत मुंगेली जिले के 41 शासकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालन हेतु स्वीकृत 82 लाख की राशि को लेकर लंबे समय से चल रही अनुमोदन की स्थिति पर अब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है।जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली द्वारा कलेक्टर जनदर्शन पोर्टल पर पत्र क्रमांक 906 अपलोड कर उक्त शिकायत निराकृत किया गया है जो की संदेहास्पद दायरे में है जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, रायपुर द्वारा व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत 41 विद्यालयों के लिए **Office E&penses/ Contingencies School** मद में प्रति विद्यालय ?2 लाख की दर से कुल 82 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि को संबंधित विद्यालयों के **PFMS** खाते में आवंटित किया जाना है।जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि उक्त राशि की क्क्नरू लिमिट जारी करने हेतु नियमानुसार आवश्यक अनुमोदन प्रक्रिया प्रचलन में है। अनुमोदन पूर्ण होते ही संबंधित विद्यालयों को तत्काल **PFMS** के माध्यम से आवंटन सीमा जारी कर दी जाएगी।यह पत्र कलेक्टर जनदर्शन, मुंगेली में प्रस्तुत शिकायत के संदर्भ में जारी किया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था कि दो माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद स्वीकृत राशि की लिमिट जारी नहीं हुई है, जिससे व्यावसायिक शिक्षा का संचालन प्रभावित हो रहा है।जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि राशि जारी करने की प्रक्रिया विभागीय नियमों के अंतर्गत चल रही है तथा अनुमोदन पश्चात विद्यालयों को लाभ मिल जाएगा।इस विषय में शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि **PFMS** प्रक्रिया में तकनीकी व प्रशासनिक औपचारिकताएं पूर्ण होते ही राशि जारी कर दी जाएगी, जिससे जिले के 41 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों को गति मिल सकेगी।उल्लेखनीय है कि यह मामला सीधे तौर पर विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित से जुड़ा हुआ है, इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का आश्वासन दिया गया है।अब देखना यह होगा कि विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद वास्तविक रूप से कब तक 41 विद्यालयों के खातों में 82 लाख की **PFMS** राशि जारी हो पाती है और व्यावसायिक शिक्षा का संचालन पूर्ण रूप से प्रारंभ होता है।

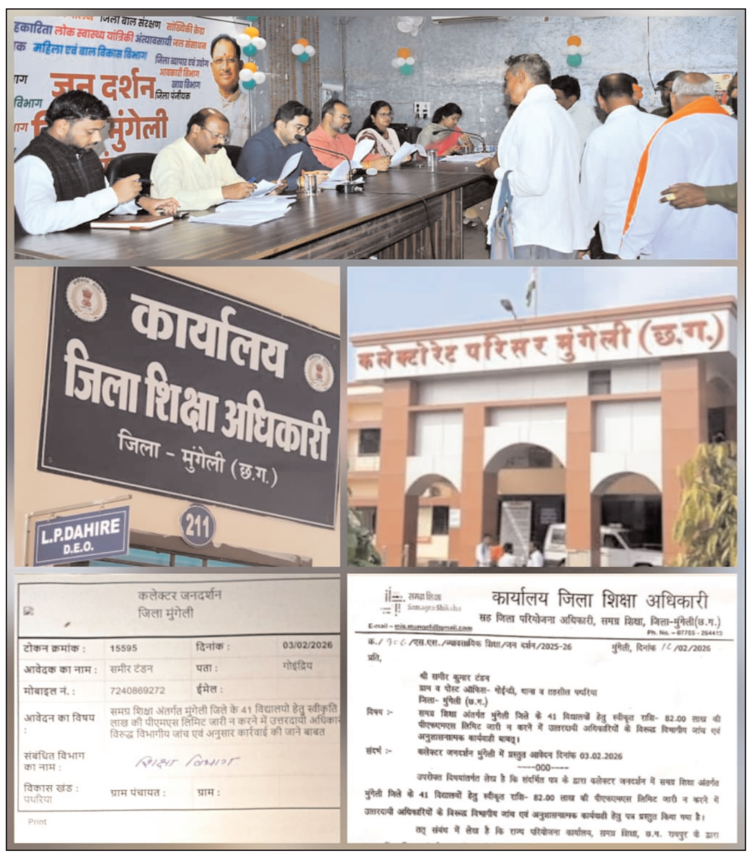

मुंगेली जिले में व्यावसायिक शिक्षा के 82 लाख तीन माह से अटके, पड़ताल में सामने आ रहा गंभीर प्रशासनिक गड़बड़ियाँ

व्यावसायिक शिक्षा समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत मुंगेली जिले के 41 शासकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्राप्त ?82 लाख की राशि अब तक विद्यालयों को जारी नहीं किए जाने को लेकर लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद राशि का आवंटन नहीं होना शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहा है।जानकारी के अनुसार केन्द्र प्रवर्तित योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय, रायपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के लिए लगभग ?23.08 करोड़ की राशि जारी की गई थी। इसी क्रम में मुंगेली जिले के 41 विद्यालयों के लिए कुल 82 लाख की राशि जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा मुंगेली को प्राप्त हुई थी। शासनादेश के अनुसार यह राशि सीधे विद्यालयों को **PFMS** प्रणाली के माध्यम से जारी की जानी थी। हालांकि शिक्षा सत्र 2025-26 अब समाप्ति की ओर है, एक सप्ताह में बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, लेकिन अब तक संबंधित विद्यालयों को राशि जारी नहीं की गई है। यदि इस समय राशि जारी भी की जाती है तो उसका वास्तविक लाभ इस सत्र में विद्यार्थियों को नहीं मिल पाएगा।सूत्रों के अनुसार राज्य परियोजना कार्यालय से जिलों को प्राप्त आहरण सीमा को अधिकतम पांच कार्य दिवसों के भीतर विद्यालयों को जारी किया जाना आवश्यक होता है। निर्धारित समय सीमा में राशि जारी नहीं होने की स्थिति में राज्य कार्यालय यह मानकर राशि वापस ले सकता है कि जिला स्तर पर इसका उपयोग नहीं किया जाना है, जो गंभीर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।बताया जा रहा है कि इससे पूर्व भी जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा मुंगेली द्वारा बीआरसी मद, केजीबीवी एवं अन्य अनुदानों की राशि समय पर जारी नहीं की गई थी, जिसके कारण लगभग 1.5 करोड़ की राशि राज्य कार्यालय द्वारा वापस ले ली गई थी। इसका सीधा असर बीआरसी के अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों एवं केजीबीवी में अध्ययनरत छात्राओं पर पड़ा था।

इस पूरे मामले में जब जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मिशन समन्वयक से जानकारी ली गई तो उन्होंने यह कहते हुए स्थिति स्पष्ट की कि लिमिट फाइल उच्च अधिकारियों — जिला मिशन डायरेक्टर, कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को भेजी जा चुकी है, जहां यह प्रक्रिया में लंबित है। पड़ताल में यह भी सामने आया है कि उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई जानकारी के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा मुंगेली के पत्र क्रमांक 794 के माध्यम से सभी 41 विद्यालयों के प्राचार्यों से व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित तीन बिंदुओं पर अनिवार्य दिनांक 5/1/2025 तक अनिवार्य रूप से जानकारी मांगी थी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा जिला मुंगेली के पत्र क्रमांक/ 552/ एस.एस./व्यावसायिक शिक्षा /2025-26 मुंगेली दिनांक 22/01/2026 व्यावसायिक शिक्षा के बेहतर क्रियान्वयन एवं सुचारु संचालन हेतु आवश्यक जानकारी के साथ समीक्षा बैठक दिनांक 23/.01./2026 को दोपहर 3:00 बजे पीएम श्री सेजेस विद्यालय दाउपारा मुंगेली में आयोजित किया गया निम्नलिखित जानकारी के साथ निर्धारित तिथि व समय पर समीक्षा बैठक में सहभागिता सुनिश्चित करें पहले उक्त राशि से किए जाने वाले कार्य का बिंदु वार विवरण, विद्यालय में संचालित ट्रेडवॉर, कक्षावार दर्ज संख्या, विद्यालय में कार्यरत ट्रेडवॉर व्यावसायिक शिक्षक की जानकारी लेकिन इसके बावजूद अब तक राशि जारी नहीं की गई।

गौरतलब है कि राज्य परियोजना कार्यालय ने अपने आदेश क्रमांक 5055 दिनांक 11 नवंबर 2025 में व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत कार्य एवं व्यय से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद जिला स्तर पर विद्यालयों को सीधे आहरण सीमा जारी करने के बजाय उनसे कार्य योजना एवं व्यय विवरण मांगा जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया और मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।सूत्रों का यह भी कहना है कि राशि को विद्यालयों को न देकर केंद्रीकृत तरीके से व्यय करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे संभावित वित्तीय अनियमितताओं की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। परत-दर-परत पड़ताल में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा मुंगेली के बीच समन्वय की कमी अथवा प्रशासनिक शिथिलता के कारण बच्चों के हित से जुड़ी यह महत्वपूर्ण योजना प्रभावित हो रही है। शिक्षाविदों का मानना है कि यदि समय रहते इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच नहीं कराई गई, तो शासन की महत्वाकांक्षी व्यावसायिक शिक्षा योजना जिले में केवल कागजों तक सीमित रह जाएगी और विद्यार्थियों को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे प्रकरण में कब तक ठोस कार्रवाई करता है और 41 विद्यालयों को स्वीकृत 82 लाख की राशि वास्तव में कब जारी होती है।

संक्षिप्त-खबर

3 दिवसीय जुंबा योगा इवेंट का भव्य समापन

बालोद (समय दर्शन)। गुरु ग्रेस योग एंड वैलनेस टीम व ज़िला प्रशासन बालोद के सहयोग से संचालित जुंबा एवं योग का अंतिम दिवस काफी उत्साहवर्धक रहा। जिसमे करीब 1200 बालोद वासियो ने एक साथ योग कर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया ।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ चेयरमैन तोमन साहू, अध्यक्ष डॉ श्री प्रदीप जैन ,विशेष अतिथि डॉ श्री महीश्वर व चेतन पटेल सुमित शर्मा सुरेश निर्मलकर सहित अन्य उपस्थित रहे ।

योग प्रशिक्षक धीरज शर्मा द्वारा जुंबा डांसिंग अभ्यास से कार्यक्रम का शुभारंभ? किया गया। प्रतिदिन मंच पर गुरु ग्रेस योगा एंड वैलनेस के सभी योगिनी ने अपने अपने डेमोंस्ट्रेशन दिए। प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस के जवान, पत्रकार वर्ग, गणमान्य नागरिक एवं व्यवसायी वर्ग सहित स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं का योग के प्रति लगाव एवं उत्साह देखने लायक था। प्रशिक्षक धीरज शर्मा के साथ डांसिंग बीट वाली धुनों पर जुंबा डांसिंग में लोगों ने जमकर पसीना बहाया एवं योग अभ्यास के लिए शरीर को तैयार किया। तत्पश्चात सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास कराया गया। इस आयोजन में बालोद के अतिरिक्त दुर्ग, भिलाई, दल्ली राजहरा, अर्जुंदा वीटी लोहारा से भी लोग शामिल हुए। करीब डेढ़ घंटा चले इस योग अभ्यास के पश्चात आयुष विभाग की ओर से पौष्टिक स्वल्पाहार अंकुरित अनाज एवं स्वास्थ्य वर्धक काढ़ा की व्यवस्था सभी के लिए की गई थी । कार्यक्रम का विशेष आकर्षण विभिन्न श्रेणियां में लकी ड्रा के माध्यम से विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। जिसमें बेस्ट ड्रेस अप एवं बेस्ट परफॉर्मेंस महिला व पुरुष वर्गों में प्रदान किया गया। अतिथि उद्बोधन में डॉ प्रदीप जैन जी ने योग के वैज्ञानिक लाभ पर प्रकाश डालते हुए, सभी को योग करने के लिए प्रेरित किया। वही मुख्य अतिथि तोमन साहू ने कहा कि यह आयोजन बालोद के लिए एक प्रेरणा है। और जल्द ही हम इससे कई गुना बड़ा आयोजन करेंगे जिसमें 21000 से अधिक लोग शामिल होंगे। इसी कड़ी में तोमन साहू जी ने योग के महत्व को बताते हुए बालोद शहर में बेहतरीन योगाभ्यास कार्यक्रम स्व-अवेक आयोजन के लिए गुरु ग्रेस योगा एंड वैलनेस टीम को बधाई व शुभकामनाएं दी। अंतिम दिवस के योगाभ्यास की समाप्ति पर सभी प्रतिभागियों ने आयोजक टीम को हृदय से धन्यवाद दिया।

22 को छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की बैठक रायपुर में

गरियाबंद (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर एवं छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ रायपुर का संयुक्त बैठक तूता रायपुर में 22 फरवरी को होगी 18दिनो तक चली सफल आंदोलन और धान खरीदी के बाद यह संगठन की पहली बैठक होगी यह बैठक अति महत्वपूर्ण हो रही है क्योंकि आंदोलन रत कर्मचारियों से आंदोलन स्थगन के समय जो सहमति बनी थी आज तक पूर्ण नहीं हुआ है लंबित चारों मांगों पर चर्चा होगी साथ ही एस्मा खत्म होने के बाद भी आज तक कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया है कर्मचारियों के बहाली के बारे में चर्चा होगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग -53 पर भीषण हादसा: बाइक सवार दो लोगों की मौके पर मौत

महासमुंद। नेशनल हाईवे-53 पर गुरुवार देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है।

मामला बसना थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार छुईपाली टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ, जहां गौरटेक निवासी परमानंद भोई (60) और उपेश नाग (34) बाइक से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर से जा टकराई, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े।

महायज्ञ और समाधि निर्माण कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक डॉ. संपत अग्रवाल, 'उपदेशमृत वाणी' का किया विमोचन

विधायक,बोले-संतों का सानिध्य ही क्षेत्र की सुख-समृद्धि का आधार

बसना (समय दर्शन)। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दुकदपाली में अध्यात्म और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ आयोजित विश्व शांति ब्रह्म महायज्ञ एवं महिला बाल लीला के पावन अवसर पर प्रातः स्मरणीय महंत दास बाबा जी के समाधि निर्माण कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। इस भक्तिमय कार्यक्रम में बसना विधायक डॉ. संपत अग्रवाल मुख्य रूप में सम्मिलित होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने वहाँ उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए साधु-संतों और गुरुओं का विधिवत पूजन कर उनका साधुवाद किया। इस अवसर पर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसार करते हुए विधायक डॉ अग्रवाल ने ब्रह्मवदूत वैष्णव चरण बाबा की अनमोल शिक्षाओं पर आधारित 'उपदेशमृत वाणी' का विमोचन भी किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए

विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने कहा कि आज इस पावन धरा पर विश्व शांति ब्रह्म महायज्ञ का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। संतों का सानिध्य और उनकी वाणी समाज को सही मार्ग दिखाने का कार्य करती है। यहाँ उपस्थित सभी साधुओं का आशीर्वाद ही क्षेत्र की सुख-समृद्धि का आधार है। महंत दास बाबा जी की समाधि आने वाली पीढ़ियों के लिए श्रद्धा और शांति का केंद्र बनेगी।

विधायक डॉ. अग्रवाल ने अपनी चर्चा को विस्तार देते हुए गहराई से कहा कि समाज में आध्यात्मिक चेतना का संचार होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रह्मवदूत वैष्णव चरण बाबा की शिक्षाएं केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि वे उन्नत जीवन जीने का एक संपूर्ण दर्शन हैं उनकी 'उपदेशमृत वाणी' जब जन-जन के हृदय तक पहुँचेगी, तो निश्चित ही समाज में उच्च नैतिक मूल्यों और मानवता का विकास होगा। क्षेत्र के विकास और धर्म के अंतर्संबंधों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आगे कहा कि राजनीति वास्तव में सेवा का एक माध्यम है, लेकिन धर्म और अध्यात्म ही वह मूल आधार हैं जो हमें उस निष्काम सेवा को करने की आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं।

आजादी के 77 वर्ष बाद भी जर्जर मार्ग से परेशान है ग्रामीण -राजेश साव

पिथौरा(समय दर्शन)। जिला महासमुंद विकासखण्ड पिथौरा के वन कक्ष क्रमांक 256 पिपरौद, एवं कंचनपुर वन कक्ष क्रमांक 287 की है ।मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण कई वर्षो से जिला कलेक्टर, फॉरेस्ट विभाग एवं क्षेत्र के विधायक जनप्रतिनिधियों को भी इस विषय के सम्बंध में अधिकारीयो को जर्जर मार्ग की सुदृढ़ीकरण को लेकर अवगत कराया गया है ।

ग्रामीणो ने बताया कि, शासकीय इमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस को फोन के माध्यम से बुलाने पर सड़क खराबी के चलते एम्बुलेंस भी समय पर

नहीं पहुंच पाती। जिसके चलते मरीज की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है । इसी रास्ते से होकर हमारे क्षेत्र के बच्चे शासकीय हाईस्कूल सांकरा एवं कालेज के लिए पिथौरा जाने का मुख्य मार्ग है।

कई बच्चे के पालक जर्जर मार्ग से परेशान होकर पढ़ाई लिखाई बंद करा कर घर घरगृहस्थी, खेती किसानी सम्हालने तक सीमित रखने मजबूर हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर आस पास के वन मार्ग में प्रधानमंत्री सड़क योजना बन सकता है तो हमारे लिए भेद भाव क्यों?

अगर बारिकपाली , पंडरीपानी , कंचनपुर से पिपरौद एवं कंचनपुर से पौसराडिपा तक मार्ग बनती है तो क्षेत्र की विकास बढ़ने की संभावना है। बच्चे पढ़ लिखकर क्षेत्र का नाम रौशन करेंगे। बच्चो व पलको का सपना साकार हो सकता है । लेकिन जर्जर मार्ग के चलते कंचनपुर से सांकरा 14 एवं पंडरीपानी से सांकरा की दूरी 16 किलोमीटर तय करना पड़ता है। आजादी के 77 वर्ष बाद भी ग्रामीण गढ्ढो से भरे जर्जर मार्ग पर चलने को मजबूर है। ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना का सपना सायद सपना बनकर ही रह जायेगा। लोगो की उम्मीद है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन से भरोसा उठने लगा है।

गढ्ढो में तब्दील मार्ग में चलना दूभर हो रहा है। पंडरीपानी, बारिकपाली , कंचनपुर , पौसराडिपा , मोहगांव , छुवालिपतेरा , धरमपुर जैसे दस गाँव के ग्रामीणों को रास्ता चलने पर कदम -कदम पर खतरा बना रहता है । राहगीर जान जोखिम में डालकर गढ्ढे से भरे जर्जर मार्ग पर चल रहे है। कई बार खबरों एवं सोसल मीडिया के सुर्खियों पर चर्चित है , सम्बंधित अधिकारियों के ज्ञापन देते देते कई वर्ष लग गए ।क्या ग्रामीणों का सपना कागजी कार्यवाही और सोसल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगा। 2023 में स्कूली बच्चे एवं ग्रामीण महासमुंद कलेक्ट्रेट जाकर पूर्व कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर को सड़क निर्माण हेतु ज्ञापन सौंपा गया था । कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए सम्बंधित अधिकारियों को आदेश भी दिए थे और जर्जर सड़क का नाप इंजीनियर के द्वारा किया गया था ।

लेकिन कुछ दिनों बाद मामला थम ही गया । आखिरकार मार्ग बनेगा तो कब ? प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ मिलेगी भी या नहीं भगवान भरोसे है।

मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने उक्त संबंध में रूचि दिखाई है पर,कब तक कार्य रुप में परिणित होगा यह कहना कठिन है।

वन विभाग द्वारा 2021 में पूर्व पंचवर्षीय कार्यकाल में 80 लाख रुपये का स्टिमेट पास हुवा था, जिसके बाद अब कागज तक ही सिमित रह गया है। ग्रामीणों ने इस माध्यम से बसना विधायक एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से अपील किया है कि, एन एच 53 से ग्राम कंचनपुर तक पक्की सड़क बनवाकर गांव के विकास में योगदान दें।

न्यायालय तहसीलदार मुंगेली, जिला - मुंगेली (छ.ग.)

// ईश्तहार //

रा.प्र.क्र. 202602250200032 / अ-6 / 2025-26
ग्राम- रोहराखुर्द प. ह. नं.- 13

एतद् द्वारा ग्राम रोहराखुर्द के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अश्वनी टंडन पिता/पति पूरनदास टंडन जाति सतनामी निवासी रोहराखुर्द तह. व जिला- मुंगेली, के द्वारा ग्राम रोहराखुर्द प.ह.नं. - 13 स्थित भूमि ख. नं. 507/4, 507/5, 528/6 रकबा 0.219, 0.190, 0.421 हे. का पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त संबंध में जिस किसी को भी किसी प्रकार का कोई भी दावा / आपत्ति हो तो वह स्वयं या अभिभाषक या प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 26/02/2006 को समय 11.00 बजे दिन को तहसील कार्यालय मुंगेली में दावा / आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 14/02/2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
मुंगेली

न्यायालय तहसीलदार तहसील पिपरिया जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

ईकोर्ट क्र. ...... ब/ 121 वर्ष 2025-26
ग्राम मक्के प.ह.नं. 11

// ईश्तहार //

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि- आवेदक अश्वन पिता रोहित साहू निवासी मक्के तहसील पिपरिया जिला कबीरधाम द्वारा अपने स्वयं अश्वन के जन्म प्रमाण पत्र शासकीय कार्य में आवश्यकता पड़ने से जारी कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अश्वन पिता रोहित साहू की जन्म दिनांक 05/05/2002 को ग्राम मक्के में हुआ है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा/ आपत्ति पेश करना हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर इस न्यायालय में नियत समय व तिथि तक दावा-आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 10/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय के पदमुद्रा से जारी किया गया।

पेशी दिनांक - 25/02/2026

मुहर

तहसीलदासदार
पिपरियाया

खबर-खास

संस्कार सिटी इंटरनेशनल स्कूल के प्रीतम विश्वास ने जेईई मेन्स में लहराया परचम, 98.9 परसेंटाइल के साथ जिले का नाम किया रोशन

राजनांदगांव (समय दर्शन)। शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुशासित मार्गदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले संस्कार सिटी इंटरनेशनल स्कूल, राजनांदगांव के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। विद्यालय के मेधावी छात्र प्रीतम विश्वास ने प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स में 98.9 परसेंटाइल अंक अर्जित कर न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, बल्कि समूचे जिले को गौरवान्वित किया है।

प्रीतम की यह सफलता उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत, एकाग्रता और स्कूल के सशक्त शैक्षणिक ढांचे का परिणाम है। इस कठिन परीक्षा में प्राप्त यह अंक उनकी विषयगत पकड़ और समर्पण को दर्शाते हैं।

प्रीतम की इस गौरवशाली उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंधन ने हर्ष व्यक्त किया है। प्रबंध समिति के सदस्य अतुल देशलहरा और आदित्य अग्रवाल ने छात्र की पीठ थपथपाते हुए इसे उनकी निरंतरता और जुनून का प्रतिफल बताया।

प्राचार्या श्रीमती रेखा तिवारी ने खुशी साझा करते हुए कहा प्रीतम ने जिस अनुशासन और लगन के साथ अपनी तैयारी की, यह परिणाम उसी का सुखद संगम है। संस्कार सिटी इंटरनेशनल स्कूल हमेशा से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों के लिए तैयार करने के प्रति संकल्पित रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि प्रीतम आगामी जेईई एडवांस में भी अपनी सफलता का क्रम जारी रखेंगे।

विद्यालय के शिक्षकों के अनुसार, प्रीतम कक्षा में हमेशा जिज्ञासु रहे हैं और जटिल अवधारणाओं को समझने की उनकी क्षमता असाधारण है। उनकी यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है, जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।

रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण से बालिकाएं हो रही शसक्त

पिथौरा (समय दर्शन)। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रानी लक्ष्मी बाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण जा आयोजन जिला प्रशासन एवं जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद ने मार्गदर्शन एवं निर्देशन से कूडो एसोसिएशन महासमुंद के द्वारा विकास खंड पिथौरा के अंतर्गत हायर सेकंडरी स्कूल बम्हनी,परधिया सराईपाली मैं प्रशिक्षक परमानंद चौहान द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं इस प्रशिक्षण से बालिकाओं को आत्म निर्भर एवं शसक्त कर आत्म रक्षा की कला सिखाया जा रहा है ।

जिसमे बालिकायें विपरीत परिस्थितियों में अपनी रक्षा स्वंय कर सकें यह जानकारी उपेन्द्र प्रधान सचिव कूडो एसोसिएशन महासमुंद ने दिया और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोजन विगत 10 वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो रही है जिससे पूरे छत्तीसगढ़ के बालिकाओं को लाभ मिल रहा है और आने वाले समय में एक नए समाज का उदय होगा सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए आभर प्रकट किए ।

22 को राज्य स्तरीय भारतीय बौद्ध महासभा

गरियाबंद (समय दर्शन)। जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की एकजुटता के साथ बौद्ध समाज गरियाबंद द्वारा 22 फरवरी 2026, रविवार को वन विभाग गरियाबंद के ऑक्शन हॉल में राज्य स्तरीय भारतीय बौद्ध महासभा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर समाज में व्यापक उत्साह देखा जा रहा है।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से गरियाबंद जिले के प्रथम कलेक्टर एवं वर्तमान विभागीय जांच आयुक्त दिलीप वासनीकर जी 13 वर्षों बाद जिले में आगमन कर बौद्ध महासभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ रायपुर संभाग के आयुक्त महादेव कावरे जी की भी विशेष उपस्थिति रहेगी।इसके अलावा छत्तीसगढ़ भारतीय बौद्ध समाज के प्रदेश अध्यक्ष,उपाध्यक्ष सहित प्रदेशभर के जिलाध्यक्षों की गरिमामयी उपस्थिति कार्यक्रम को विशेष बनाएगी। महासभा में भारतीय संविधान के रचयिता डॉ. भीम राव आंबेडकर एवं तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा तथा समाज में शिक्षा, संगठन और सामाजिक समरसता को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी।कार्यक्रम के आयोजकों में समस्त बौद्ध समाज गरियाबंद के जिला अध्यक्ष शिव खापर्डे,नारद मेश्राम,पंकज पाटिल,मुकेश रामटेके, नंदकिशोर फुलझले नागेश गजभिए,कमलेश रामटेके,नारद लोनहारे,शैलेन्द्र कुटारे सहित नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रीय बौद्ध समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य सक्रिय रूप से तैयारियों में जुटे हुए हैं।

माता सावित्रीबाई फुले समूह ने कराया नेत्रजांच शिविर :अनिता चौधरी

भविष्य में भी समूह द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े सेवा कार्य निरंतर किए जाएंगे

सरायपाली(समय दर्शन)। जोगनीपाली पंचायत भवन में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर जनसेवा की भावना के साथ नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन कर जयंती को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया।

इस पुनीत आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों, विशेषकर बुजुर्गों, को नेत्र स्वास्थ्य संबंधी जांच एवं परामर्श उपलब्ध कराना था। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी आंखों की जांच कराई और चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया।

यह आयोजन माता सावित्रीबाई फुले समूह द्वारा पंचायत भवन, जोगनीपाली में किया गया। शिविर के दौरान अनेक बुजुर्गों ने नेत्र जांच का लाभ उठाया। ग्रामीण क्षेत्र में नेत्र संबंधी समस्याओं को देखते हुए यह पहल अत्यंत सराहनीय रही। जांच के दौरान दृष्टिदोष, मोतियाबिंद के प्रारंभिक लक्षण तथा आंखों से संबंधित सामान्य रोगों की पहचान की गई और आवश्यक सुझाव दिए गए। जरूरतमंदों को आगे के उपचार हेतु निशुल्क अस्पताल भेजा गया।

इस स्वास्थ्य शिविर में त्रिलोचन नेत्रालय के सहयोग से अनुभवी चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम ने अपनी सेवाएं दीं।

नेत्रालय की टीम ने आधुनिक उपकरणों के माध्यम से आंखों की जांच कर ग्रामीणों को नि:शुल्क परामर्श दिया।इस अवसर पर माता सावित्रीबाई फुले समूह की अध्यक्ष एवं समाजसेविका श्रीमती अनिता चौधरी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज की स्थापना करने वाले वीर योद्धा थे। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर समाज को स्वाभिमान और साहस का मार्ग दिखाया। अनीता चौधरी ने कहा कि शिवाजी महाराज के जन्मदिवस पर नेत्र जांच शिविर का आयोजन कर हम उन्हें सेवा कार्य के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। समाज सेवा ही महान विभूतियों के प्रति हमारी वास्तविक श्रद्धा का प्रतीक है।उन्होंने आगे कहा कि ।कार्यक्रम के दौरान माता सावित्रीबाई फुले समूह की सक्रिय सदस्याओं ने पूरे मनोयोग से शिविर की व्यवस्थाओं को संभाला। शिविर में पंजीयन से लेकर मरीजों की कतार व्यवस्था, बुजुर्गों की सहायता, दवाइयों एवं परामर्श तक हर स्तर पर सेवाभाव दिखाई दिया। इस अवसर पर समूह की सदस्य शकुंतला चौधरी, यशोदा चौधरी, शुभल्या साहू, ममता चौहान, सेतकुमारी पटेल, यशोदा चौधरी सहित अन्य सदस्यों ने सराहनीय सहयोग प्रदान किया। सभी ने मिलकर शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ग्रामीणों ने इस पहल की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि अक्सर दूरस्थ क्षेत्रों में नेत्र जांच जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पातीं। ऐसे में पंचायत भवन में शिविर का आयोजन होना बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ। कई बुजुर्गों ने पहली बार आंखों की जांच कराई और उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। इससे उन्हें समय रहते उपचार कराने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम के समापन पर आयोजक समिति द्वारा त्रिलोचन नेत्रालय की टीम, पंचायत प्रतिनिधियों तथा सभी सहयोगी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही यह संकल्प लिया गया कि आने वाले समय में भी स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता अभियान और समाजसेवा के कार्य नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे।

22 को होगी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, बेमेतरा में तीन केंद्र बनाए गए

बेमेतरा (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा -2025 का आयोजन 22 फरवरी 2026 (रविवार) को प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तथा अपराह्न 03:00 बजे से 05:00 बजे तक किया जाएगा। बेमेतरा जिले में परीक्षा के लिए तीन केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें शासकीय पी.टी.जे.एल.एन. कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा, लक्ष्मण प्रसाद बैद्य शासकीय कन्या महाविद्यालय बेमेतरा तथा शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा शामिल हैं। इन केंद्रों में कुल 1374 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर द्वारा डिप्टी कलेक्टर को परीक्षा हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा पुलिस प्रशासन के सहयोग से परीक्षा सामग्री की सुरक्षित आपूर्ति, नकल रोकने और आकस्मिक निरीक्षण के लिए एक उड़नदस्ता दल का गठन भी किया गया है।

परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच तथा फ्रिस्किंग की जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर एक पुरुष एवं एक महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे तथा महिला अभ्यर्थियों की जांच महिला पुलिसकर्मियों द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम दो घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समय पर सत्यापन और जांच की प्रक्रिया पूरी की जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बांह के वस्त्र पहनकर आने, जूते के स्थान पर चप्पल पहनने तथा किसी भी प्रकार के आभूषण न पहनने के निर्देश दिए गए हैं।

मंडी अधिकारीयों द्वारा,जाँच के नाम पर खाना पूर्ति -महेंद्र साव

बसना (समय दर्शन)। कृषि उपज मंडी बसना मे रबी फसल 2025 में खरीदी मे करोडो की मंडी शुल्क का हेरफेर की शिकायत मे जाँच करने आये सहायक प्रबंध संचालक रामकुमार वर्मा और अनुविभाग अधिकारी कौशल कुमार कृषि विपणन मंडी बोर्ड रायपुर कृषि उपज मंडी बसना पहुचे।

जहाँ पर शिकायत कर्ता महेंद्र साव का बयान लिया गया। पर बिना किसी दस्तावेज के अवलोकन किया गया,यह संदेह के घेरे मे है।

बता दे कि,कृषि उपज मंडी अंतर्गत लगभग 235 गांव आता है उक्त गांव से किसानों के द्वारा प्रति गांव लगभग 100 से 200 एकड़ और कुछ गाँवो मे उससे भी अधिक भूमि पर रबी फसल मे धान की खेती होती है ? मंडी बसना के लगभग 235

गांव मे प्रति गांव 150 एकड़ की औसत से भी किसान फसल उत्पादन करता है तो 30 से 35 हजार एकड पुरे मंडी क्षेत्र का किसानों द्वारा धान उत्पादन होता है ।वही प्रति एकड़ 20 किवंटल के औसत से 6 लाख किवंटल के आसपास धान का उत्पादन होता है, वहीं खरीफ फसल की बचत फसल को भी किसानों द्वारा स्थानीय राईस मिल व्यापारियों को बेचा जाता है। परन्तु किसानों के द्वारा जो लगभग 30 से 35 हजार एकड़ मे 6 लाख किवंटल धान मे से सिर्फ 1.5 लाख किवंटल उपज का ही मंडी शुल्क कृषि उपज कृषि उपज मंडी बसना को मिलना बताया जा रहा है ? राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत मंत्री महेंद्र साव का कहना है कि, इसका कारण साफ है, कृषि उपज मंडी अधिकारी, कुछ रसूखदार व्यापारियों के सांठ गाँठ से उक्त घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जिससे शासन को लाखो,करोडो का मंडी शुल्क का नुकसान हो रहा है, वहीं कृषि उपज मंडी बसना मे खुली नीलामी नहीं होने के कारण किसानों को अपनी फसल को औने पौने दामों में महज 1100 सौ से 1600 के बीच मे राईस मिलो मे बेचना पड़ता है ? जिससे की कृषि उपज मंडी को मिलने वाले शुल्क मे बहुत बडा नुकसान होता है और किसानों को अपने फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता ?। जिसका सीधा उदाहरण आप देख लीजिये मंडी द्वारा खरीदी बिक्री फसल की जानकारी मात्र 149809.10 (1.5लाख) किवंटल है, जिसकी जानकारी आर टी आई से प्राप्त हुआ है ? वही किसानों के द्वारा उपज की गईं फसल जो 6 लाख किवंटल के आसपास होना चाहिए,,दोनों ही आंकड़े मे बहुत बढ़ा अंतर देखने को मिल रहा है।

नक्सल क्षेत्र के स्कूलों में पहुंची नवोदय की टीम : छात्राओं को उच्च शिक्षा और प्रवेश परीक्षा के लिए किया प्रेरित

सुकमा (समय दर्शन)। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पेंटा सुकमा 1 द्वारा विकासखंड कोंटा के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में पेस सेटिंग एवं सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम 2025-26 के तहत प्रेरणादायक और सेवा आधारित गतिविधियां आयोजित की गईं। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रभारी प्राचार्य संजय कुमार मंडल ने किया। कार्यक्रम प्रभारी संजय कवाड़े (टीजीटी एसएसटी) और मलय कुमार (टीजीटी आर्ट) भी टीम के साथ मौजूद रहे। टीम ने सबसे पहले शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला पेंटा, संकुल केंद्र पेंटा का दौरा किया। यहां प्रधान शिक्षिका साधना बंजारे, प्रधान पाठक कट्टम रामकृष्ण, शिक्षक कट्टम राजा और सितम एरा ने टीम का स्वागत किया। विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उन्हें नियमित अध्ययन, लक्ष्य तय करने और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करने की सीख दी गई।

इसके बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला पोलमपल्ली, संकुल केंद्र पोलमपल्ली में पहुंचकर स्टाफ से चर्चा की गई। प्रधान पाठक पुष्पलता

भारती और शिक्षक संतोष कुमार यादव से विद्यार्थियों की शैक्षणिक जरूरतों पर बात की गई। विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा जारी रखने के प्रयासों की सराहना की गई।

टीम ने कन्या आश्रम कांकेरलंका का भी भ्रमण किया। यहां प्रधान पाठक जगमोहन सिंह मरावी, प्रधान अधीक्षिका रविनंदनी ठाकुर और सहायक अधीक्षिका चित्रलेखा धुर्वे की मौजूदगी में छात्राओं से संवाद हुआ। आश्रम में दर्ज 94 छात्राओं में से 90 उपस्थित रहीं। छात्राओं को उच्च शिक्षा के महत्व और कक्षा 6वीं की नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को नोटबुक, ड्राइंग बुक और पेन जैसी शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। साथ ही नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जुड़ी आवश्यक जानकारी साझा की गई।

नवोदय की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना और समुदाय के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस तरह के प्रयास शिक्षा के उजाले को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।

प्राचार्य संजय कुमार मंडल ने बताया आगे भी जो है राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की स्थापना की जाएगी और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता स्वच्छता शिक्षा की एक नई पहल की शुरुआत की जाएगी।

केंद्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ के एमडी ठाकुर अध्यक्ष निर्वाचित,आमसभा में कई प्रस्तावों पर बनी सर्वसम्मति

दुर्ग (समय दर्शन)। केंद्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ के चुनाव में मंगलदास ठाकुर (एमडी ठाकुर) अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष ध्रुव सिंह धुर्वे, महासचिव नीलकंठ गढे, सचिव जितेन्द्र ध्रुव, कोषाध्यक्ष सीताराम ठाकुर, आडिटर रमाकांत और सलाहकार पद पर राजकुमार ठाकुर निर्वाचित हुए है। यह निर्वाचन प्रक्रिया केंद्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ के कचना धुरवा देवालय सिविल लाईन दुर्ग में आयोजित विशेष आमसभा की बैठक में चुनाव अधिकारी ऋषि कुमार ध्रुव और डॉ. यशेश्वरी ध्रुव के मार्गदर्शन में पूरी की गई। फर्म्स एवं सोसायटी इंदरावती भवन नवा रायपुर द्वारा पुनः चुनाव कराने के आदेश के परिपालन में केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव कराया गया हैं। जिसकी विधिवत सूचना फर्म्स एवं सोसायटी को प्रेषित कर दी गई है। निर्वाचन उपरांत केंद्रीय कार्यकारिणी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा आयोजित विशेष आमसभा में पदभार

भी ग्रहण कर लिया गया हैं। विशेष आमसभा में केंद्रीय गोंड महासभा के अलावा महिला प्रभार एवं युवा प्रभार का विस्तार किया गया है। जिसके अनुसार उपाध्यक्ष विकास मरकाम रायपुर, राजेन्द्र छेदावी कबीरधाम, संतराम नेताम अंबागढ़ चौकी मानपुर, प्रवक्ता विष्णुदेव ठाकुर राजनांदगांव, कार्यालय सचिव पन्ना नेताम, महिला प्रभार अध्यक्ष चंद्रिका ठाकुर दुर्ग, महासचिव भानुप्रभा नेताम, सचिव यशेश्वरी ध्रुव, कोषाध्यक्ष भीषम नागेश नगरी धमतरी, युवा प्रभार अध्यक्ष दिलीप ध्रुव चरौदा भिलाई, महासचिव तुलसी ध्रुव भिलाई, कोषाध्यक्ष युवराज कुंजाम, दुर्ग जिला अध्यक्ष राजेश ठाकुर निपानी पाटन को मनोनित किया गया है। इसके अलावा विशेष आमसभा में समाज हित में महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। जिसके अंतर्गत गोंड गोंडवाना महासभा बालोद, आदिवासी ध्रुव गोंड महासभा ओढार बांध जिला राजनांदगांव एवं आदिवासी गोंड गोंडवाना जिला महासमुंद में संचालित पंजीयन क्रमांक 2855/10 संस्था से केंद्रीय गोंड महासभा धमधागढ का कोई संबंध नही होगा, साथ ही अखिल भारतीय ध्रुव गोंड महासभा ओढार बांध जिला राजनांदगांव पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

सरस्वती शिशु मंदिर बसना मे शिशु नगरी कार्यक्रम सम्पन्न

बसना (समय दर्शन)। सरस्वती शिशु मंदिर शिशु वाटिका बसना में शिशु नगरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनीता अग्रवाल (पार्षद वार्ड क्रमांक 12) एवं विशिष्ट श्रीमती शालिनी अग्रवाल (मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष) थे। कार्यक्रम का शुभारंभ देव प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर दीप मंत्र एवं सरस्वती वन्दना के साथ किया गया।

विद्यालय के समन्वयक रमेश कर ने शिशु वाटिका के 12 आयामों के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। अतिथि उद्बोधन में मुख्य अतिथि श्रीमती विनीता अग्रवाल जी ने सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में बतायी कि यहां पढ़ाई के साथ-साथ संस्कार की शिक्षा दी जाती है। यहां भैया बहनों को प्रणाम करना सिखाया जाता है। विशिष्ट अतिथि श्रीमती शालिनी अग्रवाल के द्वारा भी सरस्वती शिशु मंदिर की प्रशंसा किया गया। कक्षा अरूण से द्वितीय के भैय्या बहनों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न झांकी प्रस्तुत किया गया। झांकी में आपरेशन सिंदूर, श्री रामदबार , श्री कृष्ण लीला एवं शिव-पार्वती आकर्षक का केंद्र रहा। आज के कार्यक्रम में नरसिंह शिक्षा समिति के अध्यक्ष रामचंद्र अग्रवाल, सचिव धनेश्वर साहू, शिशु वाटिका के संरक्षक सुभाष शर्मा, सदस्य कुमारी पुष्पा साव, सांवरमल अग्रवाल, सुभाष कुमार प्रधान, डॉ केशव साहू, प्राचार्य धनुर्जय साहू वरिष्ठ आचार्य अभिमन्यु दास एवं विद्यालय के समस्त दीदी-आचार्य , समस्त भैय्या-बहन एवं 115 अभिभावक उपस्थित थे।

संस्कार सिटी कॉलेज में नाड़ी विशेषज्ञ द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता व्याख्यान

राजनांदगांव (समय दर्शन)। संस्कार सिटी कॉलेज ऑफएजुकेशन, ठाकुरटोला में मंगलवार, 17 फरवरी 2026 को दवा नहीं, दिनचर्या चाहिए : वात, पित्त, कफ और औषधीय रसोई विषय पर एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य विशेषज्ञ डॉ. गणेश पांडेय ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. गुरप्रीत कौर और मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्जवलित कर सरस्वती पूजन से हुआ। इसके बाद, प्राचार्य डॉ. गुरप्रीत कौर ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए पौधा भेंट किया। प्राचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, और हमें इसे अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उनका मानना था कि ये पद्धतियाँ न केवल शरीर बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं। मुख्य वक्ता डॉ. गणेश पांडेय ने नाड़ी परीक्षण की महत्ता पर चर्चा करते हुए इसे एक प्राचीन और प्रभावी पद्धति बताया, जिससे शरीर की विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थाओं का आकलन किया जा सकता है। उन्होंने छात्रों को संतुलित आहार, प्राकृतिक जीवनशैली और नियमित दिनचर्या को अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने नाड़ी परीक्षण कराए और स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए। छात्र-छात्राओं ने भी अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त की और कई सवाल पूछेए जिनका समाधान डॉ. पांडेय ने दिया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। सहायक प्राध्यापक श्रीमती रेणुका साहू ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के छात्रों को एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था और इसमें विद्यार्थियों की उत्साही भागीदारी देखी गई।

विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

बेमेतरा (समय दर्शन)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा संचालित ''स्टेट प्लान ऑफएक्शन कैलेंडर 2026'' के अनुसार 20 फरवरी को ''विश्व सामाजिक न्याय दिवस'' के अवसर पर अध्यक्ष/प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती सरोज नन्द दास जी के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन नगर पंचायत कुसमी, ग्राम जामगांव, मजगांव, पंडरमठा, पेण्डीतराई, मोहगांव (साजा) में किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को अधिकार मित्रों द्वारा बताया गया कि सामाजिक न्याय का अर्थ समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान देना है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है, जिसके अन्तर्गत गरीबी, बहिष्कार, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी, मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। शिविर में सामाजिक न्याय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने मानवाधिकारों और आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताये, जब समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होता, तभी सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय स्थापित होता है। सामाजिक न्याय केवल कानून बनाने से नहीं आता, बल्कि समाज की सोच बदलने से आता है। कार्यक्रम में नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित जागरूकता, संवाद, डॉन योजना, घरेलू हिंसा अधिनियम, लोक अदालत, मध्यस्थता, भरण-पोषण अधिनियम, महिलाओं के अधिकार, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिनियम, हिट एण्ड रन स्कीम योजना, नवीन मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर आमजनों को जागरूक किया गया।

शासकीय प्राथमिक शाला सिलदहा का शैक्षिक भ्रमण प्रकृति और इतिहास का अद्भुत संगम

मुंगेली(समय दर्शन)। मुंगेली जिला विकास खण्ड पथरिया परिक्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला सिलदहा के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने हाल ही में एक शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया गया। इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को प्रकृति, पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जागरूक करना था।

भ्रमण की शुरुआत बाबा डोंगरी गुफा से हुई, जहां छात्रों और शिक्षकों ने सरस्वती माता, दुर्गा माता, और भोलेनाथ के दर्शन किए। इसके बाद, पहाड़ों में स्थित शक्तिपीठ शाकंभरी माता और भुवनेश्वरी के मंदिरों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। प्रधानपाठक ने शाकाहारी जीवन को अपनाने का संकल्प बच्चों से दिलवाया, जबकि खुड़िया संकुल समन्वयक विनोद सिंह ने खुड़िया बांध की ऐतिहासिक और पर्यावरणीय विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। इस बांध की विशालता और सुंदरता ने बच्चों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भ्रमण के दौरान छात्रों ने खुड़िया बांध के किनारे स्थित प्राकृतिक स्थलों का आनंद लिया, और बाद में अचानकमार अभ्यारण्य में जंगल सफारी की। यहां के सुंदर पेड़-पौधे और जंगली जीवन को देखकर बच्चों को प्रकृति के महत्व का अहसास हुआ। विशेष रूप से झिरिया के प्राचीन शिव मंदिर और जल स्त्रोत ने छात्रों को ठहरने और उनकी शांतिपूर्ण सुंदरता का आनंद लेने के लिए प्रेरित किया।

इसके बाद, डोंगरीगढ़ में स्थित भुवनेश्वरी माता के दर्शन किए गए, और प्रधानपाठक संजय सिंह ने हनुमान जी और अर्द्धनारेश्वर शिव के महिमा के बारे में बच्चों को बताया।

खबर-खास

पितृसत्ता एवं जेंडर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण

गरियाबंद (समय दर्शन)। लोक आस्था सेवा संस्थान के द्वारा पीएचएफके सहयोग से पितृसत्ता एवं जेंडर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण होटल सिटी रिजेंसी गरियाबंद में आयोजित किया गया जिसमें छूरा और गरियाबंद ब्लॉक से संगवारी महिला मंच के 50 से ज्यादा महिला मुखिया और किशोरियां शामिल हुई । प्रशिक्षण की शुरुवात संस्था सचिव लता नेताम और अध्यक्ष हेम नारायण मानिकपुरी के द्वारा सभी के परिचय के साथ शुरुआत किया ।इसके बाद प्रशिक्षक सच्चिदानंद और विजय ने जेंडर को प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियो के द्वारा सरल एवं सहज तरीके समझाया जिसमें बताया कि प्रकृति ने मनुष्य को महिला और पुरुष के रूप में जन्म दिया है। लेकिन समाज में कैसे दोनों को भेदभाव किया गया ।जेंडर क्या है,जेंडर को कई खेल और एक्टिविटी के माध्यम से समाज में जो जेंडर असमानता है उसके बारे में बताया गया जेंडर को चित्र के माध्यम से रेखांकित किया गया जेंडर और लिंग को परिभाषित करते हुए एक प्राकृतिक है और एक सामाजिक है जो सामाजिक है वही जेंडर है जिसमें बदला जा सकता है फिर पितृ सत्ता के बारे में बताया गया जिसमें पितृ सत्ता की इतिहास अलग फिल्म रोल प्ले के माध्यम से निकाला गया कि पितृसत्ता कैसे आया इसके में बताया गया और पावर के बारे समझ बनाया गया ।उसके बारे जेंडर जो है हमारे सोच में है जिसे हमे बदलने के लिए हमे हमारे सोच में बदलाव करने की आवश्यकता है जिसे आज से ये संकल्प ले कि समाज में महिला और पुरुष में समानता लाना है तो हमे स्वयं से और अपने घर से इसकी शुरुवात करने की आवश्यकता है ।इस प्रशिक्षण में लोक आस्था के उपाध्यक्ष वंदना पाटिल और समस्त स्टाफभी शामिल रहे ।

दिव्यांग शिविर में 153 हितग्राही चिन्हांकित

दुर्ग (समय दर्शन)। एनटीपीसी-सेल कम्पनी लिमिटेड के निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) योजना तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (भारत सरकार का उपक्रम) सहायक उत्पादन केन्द्र प्लॉट नं. 40 एवं 106, औधोगिक क्षेत्र, रिछाई, जबलपुर (म.प्र.) एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 20 फरवरी 2026 को जनपद पंचायत दुर्ग छ.ग. के सभागार में दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण हेतु चिन्हांकन/मूल्यांकन तथा परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उप संचालक समाज कल्याण से मिली जानकारी अनुसार शिविर में 197 हितग्राही सम्मिलित हुए जिसका परीक्षण उपरान्त 153 पात्र हितग्राहियों को सामग्री हेतु चिन्हांकित किया गया है। उक्त चिन्हांकन/मूल्यांकन तथा परीक्षण शिविर में सुश्री प्रिया साहू, सभापति जिला पंचायत दुर्ग, श्री लोमेश चन्द्राकर एवं श्री गोकुल वर्मा, सभापति जनपद पंचायत दुर्ग श्री देवनारायण चन्द्राकर, पार्षद एवं लोक कर्म प्रभारी, नगर पालिक निगम दुर्ग, श्री हितेश देशमुख, विधायक प्रतिनिधि एवं श्री ए.पी. गौतम, उपसंचालक, समाज कल्याण विभाग दुर्ग एवं समाज कल्याण विभाग दुर्ग के अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

निगम आयुक्त ने किया सेक्टर-6 क्षेत्र का औचक निरीक्षण

भिलाईनगर (समय दर्शन)। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने आज जोन-5 अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री प्रतिक्षालय, उद्यान और टेनिस कोर्ट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को साफ-सफाई कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। एम.जी.एम. स्कूल के समीप स्थित यात्री प्रतिक्षालय के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पाया कि यात्रियों के बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां क्षतिग्रस्त हैं। उन्होंने इसे तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। सेक्टर-6 बम्लेश्वरी मंदिर के पास स्थित उद्यान का अवलोकन करते हुए उन्होंने बेहतर साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों के टहलने और बैठने के लिए वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। समीपस्थ टेनिस कोर्ट का जायजा लेते हुए आयुक्त ने खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की।

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अभियान के तहत किए गए कार्यों और गतिविधियों की दी जानकारी

जल संचय जन भागीदारी 2.0 अभियान की समीक्षा

सभी जिलों के कलेक्टर जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

दुर्ग (समय दर्शन)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल संचय जन भागीदारी 2.0 अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री श्री साय एवं केन्द्रीय मंत्री श्री पाटिल वर्चुअल जुड़े। इस दौरान बिलासपुर, दुर्ग और सूरजपुर जिले के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में अभियान के तहत संचालित कार्यों और गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की।

कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने बताया कि पहले चरण जे.एस.जे.बी. 1.0 में 5606 जल संरचनाओं के निर्माण किया गया था। वहीं अब जल संचय जन भागीदारी अभियान से 2.0 के अंतर्गत गंभीर जल संकट वाले क्षेत्रों का चिन्हांकन मनरेगा, आर.बी.एस. जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) के तकनीकी अमले द्वारा किया गया है और अब तक 18,225 रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है। जिससे भू-जल स्तर में औसतन 4.18 मीटर वृद्धि हुई। जनभागीदारी से जागरूकता के अंतर्गत एकेच गोठ एकेच पानी, बुंद-बुंद बचाबो पानी, एक सोख्ता संतान के नाम और मोर गांव मोर पानी जैसे जन-जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और कार्यों की सराहना की। उन्होंने सभी कलेक्टरों को मनरेगा के तहत जल संचय कार्यों के लिए प्राप्त राशि का पूर्ण एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती में चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज ने मनाई

शिवाजी की 396वीं जयंती पर निकाली भव्य रैली

कवर्धा (समय दर्शन)। चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज कवर्धा (युवा प्रकोष्ठ) ने महान राष्ट्रनायक एवं वीर योद्धा कुर्मी कुल शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस अवसर पर समाज के युवाओं ने भव्य मोटर साइकिल रैली निकाली और नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रैली में शिवाजी महाराज की जयकारे के साथ पूरा आसमान गूंजता रहा।

इस आयोजन में नगर सहित सभी सात उपक्षेत्रों बिरकोना, लखनपुर, मोहतरा, खरहट्टा, पलानसरी, अमलीडीह, झलमला से बड़ी संख्या में युवाओं, समाजसेवियों एवं गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मोटरसाइकिल रैली सिग्नल चौक स्थित कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास से प्रारंभ हुआ एवं नगर के प्रमुख मार्गों से होकर क्षत्रपति शिवाजी चौक पहुँचा। रैली के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, सामाजिक एकता एवं अनुशासन का संदेश दिया गया।

रैली प्रारंभ होने के पूर्व कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास में सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ता संदीप चंद्रवंशी ने शिवाजी महाराज के जीवन परिचय पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। वे माता जीजाबाई के संस्कारों एवं गुरु समर्थ रामदास के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और दूरदर्शी शासक बने। उन्होंने स्वराज्य की स्थापना कर प्रजा के हित में न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था की। युवा अध्यक्ष वीरेन्द्र चंद्रवंशी ने शिवाजी महाराज के हिंदुत्व, संस्कृति एवं धर्मरक्षा के लिए किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने सनातन संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता, मंदिरों की रक्षा एवं सामाजिक समरसता को सदैव प्राथमिकता दी। उनके आदर्श आज भी युवाओं को राष्ट्र और समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शिवाजी महाराज के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति एवं सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करना है। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों, प्रशासन एवं नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। रैली में दिनेश चंद्रवंशी पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि, चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी नगर पालिका अध्यक्ष, सचिव कैलाश चंद्रवंशी, विनोद चंद्रवंशी, दीनानाथ चंद्रवंशी, लेखु बाबा जी, सन्दीप, योगेंद्र, कैलाश, सुरेंद्र, सुदर्शन, रोमन, नरेन्द्र, गोविंद आदि उपस्थित थे।

नागरिक सहकारी बैंक दुर्ग के कमल नारायण रुंगटा लगातार पांचवी बार बने अध्यक्ष

मनोज ताम्रकार व नीलू देवांगन उपाध्यक्ष निर्वाचित, 6 प्रतिनिधि पद पर भी रुंगटा पैनल की जीत

दुर्ग (समय दर्शन)। नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग के चुनाव में कमल नारायण रुंगटा लगातार पांचवी बार अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष मनोज कुमार ताम्रकार और महिला उपाध्यक्ष श्रीमती नीलू देवांगन बनाए गए है। इसके अलावा बैंक के छः प्रतिनिधि पद पर क्रमशः धनेन्द्र कांत चंदेल जिला सहकारी संघ मर्यादित दुर्ग, संजय कुमार जैन छग राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, थानेश्वर सिंह ठाकुर छग शहरी सहकारी बैंक फेडरेशन मर्यादित रायपुर, गजेन्द्र कुमार जोशी नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड दिल्ली, संदीप जैन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग, संजय कुमार रुंगटा नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनयूसीएफडीसी) दिल्ली निर्वाचित हुए है। शुक्रवार को बैंक के अध्यक्ष पद, दो उपाध्यक्ष पद और 6 प्रतिनिधि पद के चुनाव के लिए बैंक मुख्यालय अस्पताल वार्ड पचरीपारा में शाम 4 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरु हुई। नामांकन प्रक्रिया के निर्धारित समय तक सभी पदों पर उक्त प्रत्याशियों के अलावा किसी भी अन्य प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किए जाने से अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 6 प्रतिनिधि पद के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए।

यह चुनावी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारी देवाशीष दास के मार्गदर्शन में संपन्न कराई गई। बैंक के इस चुनाव में रुंगटा पैनल की धमाकेदार जीत से उनके समर्थकों और बैंक से जुड़े सदस्यों में उत्साह का माहौल है। बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल नारायण रुंगटा, उपाध्यक्ष मनोज कुमार ताम्रकार, नीलू देवांगन समेत प्रतिनिधि निर्वाचित हुए सदस्यों को बधाईयों का तांता लगा हुआ है। रुंगटा पैनल के समर्थकों ने जीत पर मिठाई बांटकर और फटाके फोड़कर जोरदार खुशियां मनाई। इसके पहले बैंक के 12 डायरेक्टर पद के लिए हुए चुनाव में रुंगटा पैनल ने एकतरफा जीत दर्ज की थी। रुंगटा पैनल ने 12 में 10 डायरेक्टर पद पर कब्जा करने में सफलता हासिल की थी।

बैंक के अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 6 प्रतिनिधि पद के निर्वाचन के दौरान नवनिर्वाचित डायरेक्टर संजय सिंह, पवन कुमार जैन (बड़जात्या), ज्ञानेश्वर ताम्रकार,तेजबहादुर बंछोर, सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउटेंट) श्रीपाल कोठारी, अरविंद चंद सुराना,सुनीता अग्रवाल, राजेश यादव, श्रीमती वसुन्धरा चौरे, बैंक के सदस्य राजेश रुंगटा, नारायण शर्मा, दुष्यंत देवांगन के अलावा अन्य सदस्य मौजूद रहे।

मनरेगा पर गरियाबंद में कांग्रेस का बिगुल

कलेक्ट्रेट घेराव से गूंजा परिसर, केंद्र सरकार के खिलाफजोरदार हुंकार

गरियाबंद (समय दर्शन)। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनरेगा में संभावित बदलावों की सुगबुगाहट के बीच गरियाबंद में शक्ति प्रदर्शन कर सियासी माहौल गरमा दिया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पूरा परिसर गूंज उठा और भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच प्रदर्शन ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी।

प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि मनरेगा से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि योजना में जनविरोधी संशोधन किए गए तो आंदोलन सड़क से सदन तक तेज किया जाएगा।

ज्ञापन में कहा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देश की सबसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है, जिसने ग्रामीण भारत में रोजगार सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय को मजबूत किया है। कांग्रेस ने आशंका जताई कि प्रस्तावित संशोधन और वित्तीय हिस्सेदारी में बदलाव से योजना की मूल भावना प्रभावित हो सकती है। पार्टी का आरोप है कि अब तक केंद्र सरकार की 90 प्रतिशत तक की वित्तीय भागीदारी को 60:40 या अन्य अनुपात में बदलने का प्रयास राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकता है। ज्ञापन में मांग की गई कि कानून को यथावत रखा जाए तथा समयबद्ध मजदूरी भुगतान, पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण जैसी व्यवस्थाएं पूर्ववत लागू रहें।

क्षेत्रीय विधायक जनक धुर्व ने कहा कि मनरेगा गरीबों और ग्रामीण मजदूरों के जीवनयापन का प्रमुख आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से मजदूर वर्ग का भविष्य संकट में पड़ सकता है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने कहा कि योजना का नाम और स्वरूप बदलना जनभावनाओं के विपरीत है। उन्होंने राष्ट्रपति से राष्ट्रहित और जनहित को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के संशोधन पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

मनरेगा केवल एक योजना नहीं, यह श्रमिक के हाथों की आशा है, गांवों की धड़कन है और आत्मनिर्भर भारत का आधार है, वक्ताओं ने एक स्वर में कहा।

गरियाबंद में आयोजित मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हुए कलेक्ट्रेट घेराव एवं एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन राजनीतिक संदेश साफथा—मनरेगा पर किसी भी बदलाव के खिलाफसंघर्ष जारी रहेगा।

नवागढ़ जनपद में पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित

जांजगीर-चांपा (समय दर्शन)। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोकुल रावटे ने शुक्रवार को जनपद पंचायत नवागढ़ में आयोजित विस्तृत समीक्षा बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। बैठक में जनपद सीईओ, सहायक अभियंता, कार्यक्रम अधिकारी सहित सभी तकनीकी सहायक एवं रोजगार सहायकों की उपस्थित थे। बैठक में जिला सीईओ ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर, अर्थात 15 मार्च तक समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने लंबित कार्यों में तेजी लाने, मजदूरों को समय पर रोजगार उपलब्ध कराने तथा कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को कार्यस्थलों पर नियमित निरीक्षण और प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृत आवासों में हितग्राहियों को 90 दिवस की मजदूरी सुनिश्चित करने तथा निर्माणाधीन आवासों को जून माह तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया। जिला सीईओ ने कहा कि आवास निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में जल संचय एवं जनभागीदारी से संबंधित कार्यों की प्रगति पर भी विशेष चर्चा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत कार्यों की समय पर पोर्टल एंट्री सुनिश्चित की जाए।

राजस्व बढ़ाने की आड़ में बड़ा वार, शहर की पहचान पर मंडराया संकट

शहर की आत्मा घिरी संकट में: गांधी मैदान के सामने बनेंगी 48 दुकानें?

गरियाबंद (समय दर्शन)। गरियाबंद के दिल में बसे गांधी मैदान पर राजस्व बढ़ाने की आड़ में बड़ा वार होने जा रहा है। मैदान के सामने 48 दुकानों का दो मंजिला व्यवसायिक परिसर बनाने की तैयारी ने शहर में भूचाल ला दिया है। जिसे लोग अपनी पहचान, परंपरा और जनआवाज़ का प्रतीक मानते हैं, वही अब नीलामी और निर्माण की जद में है। सवाल सीधा है। क्या चंद दुकानों के लिए शहर की आत्मा दांव पर लगा दी जाएगी ?

ज्ञात हो कि नगर पालिका परिषद द्वारा गौरव पथ मार्ग स्थित गांधी मैदान के सामने डीएमएफमद से विकसित रोपण एवं सौंदर्याकरण स्थल पर व्यवसायिक परिसर निर्माण के लिए भूमि नीलामी प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी सामने आते ही नगर में असंतोष की लहर दौड़ गई है।

शहरवासियों ने एकजुट होकर नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए निर्माण प्रस्ताव पर तत्काल पुनर्विचार की मांग की। नागरिकों का साफकहना है कि गांधी मैदान केवल एक खाली जगह नहीं, बल्कि गरियाबंद की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का प्रतीक है।

गांधी मैदान वर्षभर शहर की धड़कन बना रहता है। यहां दुर्गा पूजा, दशहरा उत्सव, भागवत कथा, राम कथा, खेल प्रतियोगिताएं, जनसभाएं, शैक्षणिक आयोजन और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। बड़ी संख्या में नागरिक गौरव पथ मार्ग से इन आयोजनों को देखते और सुनते हैं। यह मैदान लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का प्रमुख मंच भी रहा है ।चुनावी सभाओं से लेकर सामाजिक आंदोलनों तक, जनभावनाएं यहीं आकार लेती रही हैं। नागरिकों का कहना है कि यदि मैदान के सामने दो मंजिला व्यवसायिक परिसर खड़ा हो गया तो इसकी सौंदर्यता, खुलापन और ऐतिहासिक गरिमा पर सीधा असर पड़ेगा। आज जो मैदान दूर से दिखता है, कल दुकानों की दीवारों में कैद हो जाएगा एक नागरिक ने आक्रोश जताते हुए कहा।

प्रस्तावित 48 दुकानों के निर्माण के बाद पार्किंग की समस्या विकराल रूप ले सकती है। आशंका जताई जा रही है कि व्यापारी और ग्राहक वाहन खड़े करने के लिए मैदान का ही उपयोग करेंगे। इससे न केवल यातायात बाधित होगा, बल्कि बड़े आयोजनों के दौरान अव्यवस्था और जाम की स्थिति भी बन सकती है।

स्थानीय लोगों का तर्क है कि शहर पहले से ही सीमित यातायात व्यवस्था से जूझ रहा है। ऐसे में एक बड़े व्यवसायिक परिसर का निर्माण समस्या को कई गुना बढ़ा देगा।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि दुकानों के पीछे कचरा फेंकने, गंदगी फैलने और असामाजिक गतिविधियों के बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अन्य स्थानों के उदाहरण देते हुए नागरिकों ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों के पास व्यावसायिक निर्माण से अक्सर वातावरण दूषित होता है और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ती हैं।

स्वामित्वधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक रोहित खड़तकर द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स ग्राम छाटा, पोस्ट देवादा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) 491111 से मुद्रित कर बी-4, प्रेस काम्प्लेक्स, इंदिरा मार्केट, दुर्ग छ.ग. 491001 से प्रकाशित। संपादक :- रोहित खड़तकर,
समाचार संपादक : दामोदर राव, फोन नं.-0788-4051213, मो. 9827104452, रायपुर कार्यालय:-0771-4218364, ईमेल - samay.darshan191@gmail.com पं. क्र. CHHHIN/2011/41517 डाक पंजीयन क्रमांक छ.ग./दुर्ग/61/2024-26

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

विश्वास निर्माण गौरव
विष्णु का सुशासन

समावेशी विकास और जनकल्याण का आधार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

महिला सशक्तीकरण

महतारी वंदन योजना
68.39 लाख
महिलाओं को 24 किस्तों में कुल
₹15,588.36 करोड़
अंतरित

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
37 लाख
से अधिक महिलाएं लाभांवित

महतारी सदन
368 महतारी सदनों
के निर्माण हेतु
₹108.78 करोड़
स्वीकृत

युवा सशक्तीकरण

आयु सीमा
सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में
5 वर्ष की छूट

पदों पर भर्ती
लगभग 32,000
रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी

उद्यम क्रांति योजना
स्वरोज़गार के लिए
50% सब्सिडी
पर ब्याज मुक्त ऋण

किसान कल्याण

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
26 लाख
किसान लाभांवित

धान
₹3100/क्विंटल और
21 क्विंटल/एकड़
की दर से धान खरीदी

बैंक राशि
दो वर्षों में किसानों के खातों में
₹1.50 लाख करोड़
से अधिक की राशि अंतरित

औद्योगिक विकास

नई औद्योगिक नीति लागू
₹7.83 लाख करोड़
से अधिक का मिला निवेश प्रस्ताव

औद्योगिक हब
नया रायपुर
बन रहा औद्योगिक हब

चिप यूनिट
₹1100 करोड़
की लागत से चिप यूनिट स्थापित

26 लाख
से अधिक आवास स्वीकृत

400 से अधिक
प्रशासनिक सुधार से निवेश की राह आसान

पारदर्शिता लाने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन

₹51,080 करोड़
से रेल परियोजनाओं का हो रहा क्रियान्वयन

₹40 हज़ार करोड़
से अधिक लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का हो रहा विकास

सरल, सहज और उदार व्यक्तित्व वाले माननीय मुख्यमंत्री
श्री विष्णु देव साय जी को हार्दिक शुभकामनाएं

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in